



Amruta Khanvilkar Thinks Actors...

SHARE
सेंसेक्स : 83,817.69
निफ्टी : 25,776.00

SARAFI
सोना : 14,865
चांदी : 320.00

(नोट : सोना 22 केरट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

तुर्की जा रहे विमान में आग, इमर्जेंसी लैंडिंग

KOLKATA : हवा में एक बड़ा हादसा टल गया। तुर्की एयरलाइंस के एक विमान में सवार 236 यात्रियों और क्रू मेंबरों ने तब राहत की सांस ली, जब विमान ने कोलकाता के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। विमान के एक इंजन में आग की चिंगारी देखने के बाद पायलट ने इमर्जेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी और कोलकाता एयरपोर्ट ने सारी इमर्जेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर विमान को सुरक्षित उतारने में मदद की। नेताजी राजधानी काठमांडू से तुर्की के इस्तांबुल जा रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट की कोलकाता में बुधवार को इमर्जेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में आग लगने की सूचना मिलते ही कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमर्जेंसी लैंडिंग करायी गयी। विमान में 236 यात्री सवार थे। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।

बंगाल को बनाया जा रहा निशाना : ममता बनर्जी

KOLKATA : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सुविधियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में स्वयं अपनी दलीलों को रखा और निर्वाचन आयोग पर राज्य को कथित तौर पर बेवजह निशाना बनाने और वहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने न्यायालय को लोकतंत्र की बचाने और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सुविधियों के निष्पक्ष एसआईआर को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने एक बार निर्वाचन आयोग को हटाने का आग्रह किया था, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को हटाने पर कथित रूप से भेजे जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था।

साइबर ठग के कई गिरोहों का भंडाफोड़, 55 गिरफ्तार

NEW DELHI : दिल्ली पुलिस ने एक महीने तक चले अभियान के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोहों का भंडाफोड़ करते हुए 55 लोगों को गिरफ्तार किया और चोरी की गई राशि में से 4.84 करोड़ रुपये बरामद किए, जबकि 1.55 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि विनीत लैन-देन के विशेषण और कई राज्यों में समन्वित क्षेत्रीय अभियानों के बल पर सफलता मिली। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) डी. शरद भास्कर ने एक बयान में कहा, इस अवधि के दौरान अदालती आदेशों के माध्यम से पीड़ितों को लगभग 39 लाख रुपये वापस किए गए, जिससे फर्जी निवेश और ट्रेडिंग योजनाओं के लिए डिजिटल असेट का उपयोग कर-के विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठग गए लोगों को आशिक राहत मिली।

विपक्ष के हंगामे से लोकसभा स्थगित, टला पीएम का संबोधन

NEW DELHI @ PTI : बुधवार को विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। इसके बाद शाम 5 बजे सदन को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के कारण पीएम नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन भी टल गया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिलने और आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में कुछ कितानों का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण भी सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर देने वाले थे जवाब, स्पीकर के ऑफिस में विपक्षी और बीजेपी सांसदों के बीच भी हुई तीखी बहस

नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिलने और आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर बनी हुई है गतिरोध की स्थिति

मर्यादित आचरण सभी की जिम्मेदारी

संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के ऑफिस में विपक्ष और बीजेपी सांसदों के बीच भी बहस हुई। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन के अंदर मर्यादित आचरण और व्यवहार करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने पांच मिनट बाद ही बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।



भारत-अमेरिका ट्रेड डील की दी गई जानकारी

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामा होने पर दोपहर 2 बजे तक और 2 बजे दोबारा शुरू होकर 8 मिनट में ही रुक गया। शाम 5 बजे फिर शुरू होने के बाद भी हंगामे के चलते लोकसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इधर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सदस्यों

की नारेबाजी के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है। भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। यह डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे।

देश में हो रही बुलडोजर पॉलिटिक्स : खड़गे

राज्यसभा में भी ट्रेड डील की जानकारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आरोपों पर जेपी नन्दा ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ट्रेड डील में किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखित में कहा जा चुका है। तब भी आप बार बार किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश खतरनाक दौर से गुजर रहा। भारत की पहचान डाइवर्सिटी और थॉट्स की प्रैक्टिस रही है। उत्तराखंड में सड़कबंदी को मार दिया गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे सुरक्षा मिलेगी। आपके पास सहिष्णुता नहीं है। आप केवल वोटों के लिए लड़ते हैं। भाजपा के एक सीएम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। ये सीएम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। देश में सिलेक्टिव टार्गेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। नन्दा जी आपकी मजबूरी है कि मोदी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी केरल में चुनाव आने पर वचन में जाते हैं लेकिन उन पर होने वाले अत्याचार पर खामोश रहते हैं। इसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना भाजपा के लोगों को खाना हजम नहीं होता। आपको पावर मिला है उसका टीक से इस्तेमाल करो देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

धनबाद के गोल्फ मैदान में झामुमो ने मनाया 54वां स्थापना दिवस, सीएम हेमंत बोले-

जनता के दम पर पूरी दुनिया में बजने लगा है झारखंड का डंका

PHOTON NEWS DHANBAD :

बुधवार को धनबाद के गोल्फ मैदान में झामुमो का 54वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। इस समारोह में दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारतरत्न देने की आवाज उठी। उल्लेखनीय है कि इस साल केंद्र सरकार ने मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जनता के दम पर झारखंड का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरे राज्य के चौरफा विकास के लिए हर स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनता को जोहार बोलने के बाद कहा कि यह जोहर झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश में इस जोहार को सम्मान और समर्थन मिला है। लंदन में भी लोग जोहार बोल रहे हैं। सीएम ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनता को जोहार बोलने के बाद कहा कि यह जोहर झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश में इस जोहार को सम्मान और समर्थन मिला है। लंदन में भी लोग जोहार बोल रहे हैं। सीएम ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

धीरे-धीरे विदेश तक पहुंच चुका है जोहर का समर्थन और सम्मान

इस प्रदेश को हासिल करने के लिए आंदोलनकारियों ने लड़ी लंबी लड़ाई

अब राज्य के चौरफा विकास के लिए हर स्तर पर लगातार किए जा रहे प्रयास

यह केवल स्थापना दिवस ही नहीं, इस बार गुरुजी के नहीं रहने का भी दिन

राज्य को सजाने-संवारने व गुरुजी के सपनों को पूरा करने का आज संकल्प दिवस भी



अब विदेश में भी पढ़ाई करने जा रहे प्रदेश के बच्चे

हेमंत सोरेन ने कहा कि जब अलग झारखंड राज्य का आंदोलन शुरू हुआ तो कितने लोग इस मिश्री में मिल गए, तब यह राज्य मिला। तब कसा गया कि ये बोका लोग राज्य नहीं चला सकते। राज्य गठन के 15-16 सालों के बाद हमने भाजपा से सता छीनने का काम किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज युवा झारखंड अन्य राज्यों से आगे रहते।

गुरुजी के संघर्ष का नतीजा है यह राज्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूलवासी के साथ-साथ यहां जो बाहर से आए हैं, वो भी अपने आप को झारखंडी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां का ओहदा बड़ा है। झारखंड ने पूरे देश को चलाने का काम किया, पर इस राज्य के लोगों को गरीबी, यातना और अधिका मिली। इसी कारण गुरुजी ने अलग राज्य का बिगुल

फूँका। सीएम ने कहा कि यह राज्य गुरु जी के संघर्ष का नतीजा है। झारखंड के लोगों की कुबानी इसमें शामिल है। हेमंत ने कहा कि यह राज्य को सजाने-संवारने का दिन है। गुरुजी के सपनों को पूरा करने का संकल्प दिवस है। गोल्फ मैदान का स्थान पूरे राज्य में अलग है। इस घर्ती ने कई नेतृत्व दिए, जिन्होंने दमनकारी लोगों के सामने सीना तान कर अपनी कुबानी दे दी।

हमारे बीच आकर हमें पढ़ाने दिखाया। यह केवल स्थापना दिवस नहीं है, यह गुरुजी के नहीं रहने का भी दिन है।

टेस्ट मैच में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो आगना नया बैटर बदले क्रिकेट के 73 नियम, एक अक्टूबर से होंगे लागू

NEW DELHI @ PTI :

अब पूरी दुनिया में चर्चित क्रिकेट के 73 नियम बदल दिए गए हैं। नए नियम एक अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में यह सबसे बड़ा अपडेट है। बदले गए नियमों में यह तय किया गया है कि इनमें टेस्ट मैच में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर पूरा ओवर खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच, विकेटकीपर की पोजीशन जैसे कई नियम बदले गए हैं। लेमिनेटेड बैट को सशर्त

डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच संबंधी नियमों में भी परिवर्तन



मंजूरी दी गई है। क्रिकेट नियम बनाने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने अपनी

ओवरथ्रो और डेड बॉल की नई परिभाषा

एमसीसी ने कहा, यह अनुचित माना गया कि अगर दिन के अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रही टीम विकेट लेती है, तो बल्लेबाजी टीम को नया बल्लेबाज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। नए नियम के तहत अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, तो अंतिम पुरा किया जाएगा, भले ही उस दौरान विकेट गिर जाए। एमसीसी ने ओवरथ्रो और मिसफिल्ड के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। अब

ओवरथ्रो सिर्फ तभी माना जाएगा, जब कोई फील्डर विकेट पर गेंद फेंकता है और वह गेंद आगे निकल जाती है। अगर फील्डर बाउंड्री के पास गेंद रोकने की कोशिश करता है और गेंद हाथ से फिसलकर निकल जाती है, तो उसे ओवरथ्रो नहीं, बल्कि मिसफिल्ड कहा जाएगा। अब डेड बॉल के लिए यह जरूरी नहीं है कि गेंद गेंदबाज या विकेटकीपर के हाथ में ही हो।



मणिपुर के 13वें सीएम बने युमनाम खेमचंद

IMPHAL : भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने गए। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बुधवार शाम को लोकभवन में खेमचंद को गोपनीयता की शपथ दिलाई। मतेई समुदाय से आने वाले खेमचंद पूर्व सीएम बीरेन सिंह के करीबी माने जाते हैं। नया समुदाय से आने वाले लोसी दिखो को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। वे नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं। उनके अलावा कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपमेन ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शपथ ली। वे राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं। राज्य में एक बार फिर पनडिप की सरकार बनी है। आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में 356 दिन से लगा राष्ट्रपति शासन हटाया है। मणिपुर में मतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा के कारण 9 फरवरी 2025 को तत्कालीन सीएम एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। इसके 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

सेहत की चिंता भारतीय वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन के बाद किया खुलासा

नींद में गड़बड़ी के हालात से भी बढ़ सकता है कैंसर का खतरा

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

विश्व स्तर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के संबंध में लगातार शोध की प्रक्रिया जारी है। इसके कारणों और निदान के नए-नए आयुष्य को लेकर नई तकनीक का भी निरंतर विकास हो रहा है। आज के दौर में जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से अनेक प्रकार के विषम हालात पैदा हो रहे हैं और उनके कारण भी कैंसर का खतरा बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययन से हाल ही में खुलासा हुआ है कि अब कैंसर का खतरा बढ़ना सिर्फ खान-पान या अनुयायिक कारणों से ही नहीं, बल्कि बिगड़ी हुई नींद के हालात से उत्पन्न नर्वस सिस्टम के काम में आए डिस्टर्बेंस और अव्यवस्थित दिनचर्या से भी जुड़ा दिख रहा है। एम्स भोपाल के जैवरासायन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार के नेतृत्व में यह शोध हुआ है। अनुसंधान के नतीजों को अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'स्लीप मेडिसिन रिव्यूज' में प्रकाशित किया गया है, जो इसे वैश्विक मान्यता देता है। शोध में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ के डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव, मनेंद्र सिंह तोमर और मोहित का भी अहम योगदान रहा है।

अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'स्लीप मेडिसिन रिव्यूज' में प्रकाशित किए गए हैं अनुसंधान के नतीजे भोपाल एम्स के जैव रसायन विभाग के डॉ. अशोक कुमार के नेतृत्व में हुआ रिसर्च

शोध में डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव, मनेंद्र सिंह तोमर और मोहित का भी अहम योगदान



एक बायोलॉजिकल वॉच के आधार पर निरंतर काम करते रहता है मनुष्य का शरीर

सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं रोग का इलाज

ऐसे हालात में शरीर की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। शोध में यह भी सामने आया कि कैंसर कोशिकाएं शरीर की ऊर्जा व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ लेती हैं। इससे प्रतिरक्षा कोशिकाएं उन्हें खत्म करने में सफल नहीं हो पाती हैं। रिसर्च से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि कैंसर से बचाव केवल दवाओं पर निर्भर नहीं है। नियमित नींद, समय पर भोजन, संतुलित दिनचर्या इन तीनों को

अपनाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में कैंसर का इलाज व्यक्ति की नींद और दिनचर्या के अनुसार तय किया जाएगा, जिससे इलाज ज्यादा असरदार और कम दुष्प्रभाव वाला हो सकेगा। इस उत्कृष्ट शोध के लिए कुछ दिन पहले डॉ. अशोक कुमार को भोपाल एम्स में आयोजित चौथे रिसर्च डे के दौरान फेकट्टी नियमित नींद, समय पर भोजन, संतुलित दिनचर्या से सम्मानित किया गया था।

पुंदाग ओपी क्षेत्र में दिया गया वारदात को अंजाम

रांची में दो दिनों से लापता नाबालिग लड़के का मर्डर

PHOTON NEWS RANCHI :

राजधानी रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के की हत्या का मामला सामने आया है। 116 साल के जसमी मंसूरी की डेड बॉडी लाजपत नगर इलाके में स्थित एक निमाणाधीन अपार्टमेंट से बरामद किया गया है। जसमी रांची के पंडरा का रहने वाला था। शव को देख कर ऐसा लगता है कि पहले जसमी को चाकू से मारा गया और फिर हत्या के बाद मृतक को निमाणाधीन चार माले के अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही हटिया डीएसपी पीके मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। इस

● लाजपत नगर इलाके के एक निमाणाधीन अपार्टमेंट में मिली डेड बॉडी

● परिजनों ने पंडरा ओपी में गुमशुदगी का दर्ज करवाया था सहा

दौरान एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। टीम ने चाकू के निशान, खून के घब्बे समेत सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रहित किए हैं। इस संबंध में हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि मामला हत्या का है। ऐसा लगता है कि आपसी विवाद के बाद जसमी को पहले पीटा गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है।

धनबाद में नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने भया पर्चा, रही गहमा-गहमी

भाजपा समर्थित उम्मीदवार के सामने संजीव सिंह समेत तीन बागी प्रत्याशी

PHOTON NEWS DHANBAD : झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कोयलांचल की सियासत पूरी तरह गरमा गई है। बाजपा ने धनबाद में मेयर पद के लिए संजीव अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन, भाजपा के तीन बागी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में डट गए हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। साथ ही पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भी मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके अलावा, भाजपा नेता मुकेश पांडे और रघुनाथ भगत ने भी मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि अगर नामांकन वापसी के बाद भी भाजपा

गरमाई कोयलांचल की सियासत, बीजेपी में हड़कंप



नामांकन भरने जाते हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह

से जुड़े नेता मेयर पद के चुनाव में मैदान में डटे रहते हैं तो उनके ऊपर कारवाई हो सकती है। इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य

साहू ने तीनों बागी उम्मीदवारों से मिलकर नामांकन नहीं करने की बात कही थी। इसके बावजूद इन उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार अब इन उम्मीदवारों तक संदेश पहुंचाया गया है कि वह अपने नाम वापस ले लें। भाजपा आला कमान को उम्मीद है कि तीनों उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेंगे और पूरी पार्टी एकजुट होकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पीछे खड़ी रहेगी।

पहले पूर्व विधायक ने दाखिल किया नामांकन

पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे और वहां नामांकन किया। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। संजीव सिंह के नामांकन करने के दो घंटे बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने भी डीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। संजीव अग्रवाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, धनबाद के सांसद दुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे। साथ ही हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ थे।

प्रदेश अध्यक्ष ने दिए कार्रवाई के संकेत

पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि अनुशासनहीनता फतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो भी नेता अनुशासनहीनता करेगा। पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। नामांकन वापसी के बाद पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के लिए विचार करेगी।

जनता के हित के लिए लड़ रहा हूं चुनाव : संजीव

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि वह जनता के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार लंबे समय से कोयलांचल की जनता की सेवा करते हुए चल रहा है। धनबाद का विकास करना उनका मुख्य लक्ष्य है। सांसद दुल्लू महतो ने कहा कि पार्टी ने संजीव अग्रवाल को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए पार्टी पूरी तरह उनके साथ है और सभी कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल को चुनाव जिताने के लिए एकजुट हैं।

जामताड़ा से सात व मिहिजाम से 17 महिलाओं ने किया नामांकन



मिहिजाम नगर पंचायत से नामांकन दाखिल करती जयश्री देवी

JAMTARA : निकाय चुनाव को लेकर जिले में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। जामताड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। निवाची पदाधिकारी पूनम कश्यप के सामने पहले अर्चना देवी फिर बाद में भाजपा समर्थित प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष रीना कुमारी ने दूसरे सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही जामताड़ा नगर पंचायत से कुल सात महिलाओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें रीना कुमारी, मुक्ता मंडल, चमेली देवी, आशा गुप्ता, लवली दुबे, अर्चना देवी और बबिता झा हैं। दूसरी ओर मिहिजाम नगर पंचायत से कुल 17 महिलाओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसमें बुधवार को आखिरी दिन नौ ने नामांकन दाखिल कराया। इसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष जयश्री देवी, सबीहा अंजुम, पुष्पा एलिजाबेथ खाखा, नीना शर्मा, सुधा देवी, नईमा खातून, प्रीति देवी, सुनीता देवी, झामुमो समर्थित प्रत्याशी गुलशन आरा समेत नौ ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

गढ़वा में दिनदहाड़े नौ लाख रुपये के आभूषण लूटकर फरार हो गए बदमाश

घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

PHOTON NEWS GARHWA : गढ़वा जिले के बिशुनपुर में बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। लाल चौक के व्यस्त इलाके में बदमाश चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इस बैग में लगभग नौ लाख रुपये मूल्य के सोना चांदी के जेवरात और 6000 नकदी थे। यह बैग बिशुनपुरा के रहने वाले अमित गुप्ता का है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर बैग बरामद किया जाएगा। बिशुनपुरा के रहने वाले अमित गुप्ता ने बताया कि मंगलवार की शाम वह देहात से लौट कर लाल चौक स्थित मनीष पासवान की दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी कर बातचीत कर रहे थे।



पहले की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा

बताते हैं कि बिशुनपुरा में इन दिनों अपराध का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। एक माह के भीतर सोना-चांदी लूट की यह दूसरी बड़ी वारदात है। इसके पहले अपर बाजार में शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय सह ज्वेलर्स दुकान में 40 लाख रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है।

बदमाशों का किया गया पीछा लेकिन वह निकल भागे मोटरसाइकिल पर ही सोने चांदी के गहने से भरा बैग लटका हुआ था। भी बदमाश आए और बैग लूटकर फरार हो गए। जैसे ही उन्हें घटना का एहसास हुआ बदमाशों का पीछा किया गया।

लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। अमित गुप्ता ने बताया कि एक साल पहले उनकी बाइक भी चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत बिशुनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज तक पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर सकी। ना ही वाहन का सुराग मिला।

जमीन विवाद में लोगों ने युवक की पीट-पीटकर ले ली जान

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 घंटे तक सड़क जाम

PHOTON NEWS SAHIBGANJ : साहेबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद दूसरे पक्ष के गुस्साए लोग और मृतक के परिजनों ने उधवा-राधानगर मुख्य सड़क पर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। वहीं, दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा लोगों को समझा-बुझा कर प्रदर्शन को समाप्त कराया।



विरोध में टायर जलाते व प्रदर्शन करते लोग

पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम कार्तिक मंडल था। वह दक्षिण सरफराजगंज कटहल बड़ी भट्टा गांव का रहने वाला था। इस घटना के बाद पूरी इलाके में तनाव फैल गया।

घटना के बाद पूरी इलाके में तनाव फैल गया।

क्या कहना है पुलिस का
प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि इन दोनों पक्षों में विवाद काफी दिनों से चल रहा था। गत कल विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरा पक्ष के लोग युवक को लाठी डंडों से हमला कर दिया।
लोगों को हुई परेशानी
राधा नगर मुख सड़क मार्ग पर प्रदर्शन के कारण करीब दो घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। वहां की लंबी कतारें लग गई थीं। ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

BRIEF NEWS
विधायक ने मरीजों का वापस कराया पैसा



PALAMU : मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) में मंगलवार रात तिहरे हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल बच्ची के इलाज से कप्तान सहयोग के लिए पहुंचे पाकी विधायक कुशवाहा डा.शशिभूषण मेहता अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर भड़क उठे। उन्होंने अस्पताल परिसर स्थित पुराने भवन में संचालित मणिपाल हेल्थपैम जांच केंद्र पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बताया जाता है कि सतबरवा प्रखंड के धावाडीह पंचायत तथा मेदिनीनगर सदर प्रखंड के कोड्डिशा पंचायत के अत्यंत गरीब मरीजों से जांच के नाम पर करीब एक-एक हजार रुपये वसूले गए थे। विधायक ने इसे गंभीर मामला बताते हुए तत्काल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी को फोन पर बात कर स्थिति से अवगत कराया। मामले की सूचना मिलते ही एमएमसीएच अधीक्षक डा.मजय कुमार तथा उपाधीक्षक डा.आरके रंजन जांच केंद्र पहुंचे और संबंधित मरीजों को राशि वापस कराई गई। विधायक डा. मेहता ने कहा कि अस्पताल की स्थिति चिंताजनक है।

शाह स्पोर्ट्स अकादमी क्वार्टर फाइनल में



CHAIBASA : लगभग एक पखवाड़ा के बाद बुधवार से पुनः शुरू हुए 10वीं अंशक कुमार जैन जिला नॉक आउट क्रिकेट प्रतियोगिता में आज खेले गए एक रोमांचक मैच में चक्रधरपुर की शाह स्पोर्ट्स अकादमी ने टीम लारसन क्लब को एक विकेट से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। अब क्वार्टर फाइनल में शाह स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी का मुकाबला 6 फरवरी को चक्रधरपुर क्रिकेट अकादमी एवं लट्टू उरांव क्रिकेट क्लब के बीच खेले जाने वाले मैच के विजेता से 12 फरवरी को होगा। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस शाह स्पोर्ट्स अकादमी ने जीता तथा विश्वी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लारसन क्लब की पूरी टीम 29.5 ओवर में 177 रन बनाकर आल आउट हो गई। लारसन क्लब की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जन्मजय सिंह यादव ने आठ चौके की सहायता से 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। एक समय लारसन क्लब के पांच महत्वपूर्ण विकेट मात्र 54 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम का स्कोर तीन अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगा परंतु निचले क्रम में सचिन भाटी ने 37 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अन्य बल्लेबाजों में दिमांशु पांडेय ने 17, मनजय कुमार एवं अनमोल ने 16-16 रनों का योगदान दिया। शाह स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से करण कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 25 रन देकर चार विकेट चटकए।

बोकारो में आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

BOKARO : बोकारो जिला के पेटरवार थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पेटरवार थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बताते हैं कि आरोपी युवक कोलकाता-वाराणसी सिक्स लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही कंपनी में पत्थर खनन करने वाली मशीन का ऑपरेटर है। वह पीछे किशोरी के घर के पास किराए के मकान में रहता है। किशोरी के पिता मजदूरी करते हैं। घटना के दिन किशोरी घर पर अकेली



थी। पिता मजदूरी करने बाहर गए थे। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। जारीडीह सर्किल इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए थे। आरोपी को पकड़ लिया गया था और पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। किशोरी की मेडिकल जांच कराई गई है। जल्द ही उसका कोर्ट में बयान कराया जाएगा।

बिरसानगर की फर्नीचर दुकान में लगी आग

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के बिरसानगर जोन नंबर 8 में आकाश फर्नीचर नामक दुकान में मंगलवार की देर रात भयंकर आग लग गई। आग लगने की जानकारी मकान मालिक ने आकाश को दी। इसके बाद आकाश भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंचे, तो देखा की पूरी दुकान धूँ धूँ कर जल रही है। सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया है। इलाके के लोगों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश शुरू की। घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आकाश का कहना है कि आग कैसे लगी। मामला संदिग्ध है। आकाश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शाम को दुकान में अगरबत्ती जलाई थी। अगरबत्ती जब बुझ गई थी। तभी दुकान बंद की थी। इसलिए अगरबत्ती से आग लगने का सवाल नहीं है। उन्हें शक है कि किसी अराजक तत्वों ने आग लगाई है। घटना की जानकारी पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुधवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आग लगने के कारणों का पता लगा लिया जाएगा।

लेवी नहीं मिलने पर हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग

PHOTON NEWS CHATRA : चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र इलाके में मंगलवार की देर रात लेवी और रंगदारी नहीं मिलने के कारण अपराधियों ने दो निष्पाधीन साइटों पर मजदूरों से मारपीट की। वहीं नहीं उन लोगों ने भागते समय दोनों साइटों को मिलाकर तीन राउंड फायरिंग भी की, इससे मजदूरों में भय व्याप्त है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल तुरंत दलबल के साथ मौके पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मजदूरों से पूछताछ की। एसपी ने मजदूरों को आशवासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पांच की संख्या में



दहशत फैलाने के लिए चलाई गोली

अपराधी आए थे। वे सभी अपना चेहरा ढके हुए थे और हथियारों से लैस थे। वे लोग अपने को प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी का सदस्य बता रहे थे। बता दें कि बदमाशों ने पहले खडैया के कबरा पुल के पास हमला बोला। आरोपी है कि उन लोगों ने यहां दहशत फैलाने के लिए पहले एक राउंड गोली चलाई। इसके बाद मजदूरों के साथ मारपीट भी की। भागने के पहले आरोपियों ने घटनास्थल पर

रखी एक मशीन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामा करने के बाद वे लोग सीधे गरवईया टोला पहुंचे। वहां पर जल मीनार का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधियों ने इस साइट पर भी दो राउंड फायरिंग की। इसके बाद भाग गए। पुलिस ने बताया कि मजदूरों से घटना के बारे में पूछताछ करने के बाद पता चला है कि उन (अपराधी) लोगों ने भागते समय मजदूरों को अपने ठेकेदार से रंगदारी और लेवी पहुंचा देने की धमकी दी। अगर रंगदारी नहीं मिलती है तो काम बंद करने की भी चेतावनी दी। मजदूरों ने बताया कि अपराधी तीन मोबाइल नंबर दे गए हैं, ताकि, लेवी और रंगदारी देने से पहले उनसे बात की जाए।

तैयारी 13 से शुरू होगा ऐतिहासिक राजकीय जनजातीय उत्सव, मेला परिसर में प्रशासनिक गतिविधियां तेज

136 साल पुराने हिजला मेले से जुड़ी है संथाल परगना की पहचान



कार्यक्रम स्थल पर चल रहा सजावट का कार्य

PHOTON NEWS DUMKA : झारखंड की उपराजधानी दुमका शहर से सटे हिजला पहाड़ी की तलहटी में हिजला बस्ती। दुमका सदर प्रखंड की सरुवा पंचायत का एक गांव और शहर से महज चार किलोमीटर दूर। इसी बस्ती में मयूरक्षेत्र नदी तट व हिजला पहाड़ी है। तकरीबन 13 साल पुराना ऐतिहासिक राजकीय जनजातीय हिजला मेला परिसर। समय के साथ हिजला मेला परिसर की काया थोड़ी बदली है। मेला परिसर के चारों ओर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष 13

1890 में हुई थी मेले की शुरुआत

संताल परगना के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास में हिजला मेला की अपनी अलग पहचान है। क्षेत्रीय कला, रास, हर्ष, नृत्य और संगीत व सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। हिजला मेला की शुरुआत 136 साल पूर्व 3 फरवरी 1890 को ब्रिटिश हुकूमत के तत्कालीन उपायुक्त जान आर कारस्टेयर्स ने की थी। तब से मेला इस क्षेत्र की संस्कृति को कला, रास-रंग और संगीत के माध्यम से प्रदर्शित करने की परंपरा चली आ रही है। मेला का शुभारंभ किए जाने के बाद क्षेत्र के ग्राम प्रधान, मांडी, परगने के साथ ब्रिटिश हुकूमत बेटक विचार-विमर्श करते थे। इस कारण यहां बने वाली नियामवली को अंग्रेजी में हिजला ला कहा गया और धीरे-धीरे यह हिजला के नाम से पुकारा जाने लगा।

ढांचागत निर्माण से बदल गया लुक

हिजला मेला परिसर के बीच में स्थित है चांद-भैरव स्मृ कला मंच। इस मंच की उपयोगिता हिजला मेला के दौरान सांस्कृतिक आयोजनों के लिए होती है। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान यह मंच अतिथियों के लिए किया जाता है। इस मंच का उपयोग मेला में अखिल प्रतिभागियों को प्रेरक करने के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताएं व संबोधन के लिए किया जाता है। हिजला मेला संपन्न होने के बाद भी सालों भर हिजला के आसपास के ग्रामीण इलाका के निवासी इस मंच में करते हैं। इस मंच का आकार 75 फीट गूणा 25 फीट है। मेला परिसर के एक हिस्से में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण कराया गया है। प्रशासनिक भवन का आकार शंखुमुरी है। मेला परिसर के बीच-बीच स्थित जाहेश्रथान को दर्शनीय बना दिया गया है। यहां रोशनी की पुष्ता व्यवस्था और सुरक्षा के महेंजर गेट भी लग चुका है। मेला परिसर को नया लुक देने के लिए यहां एक नया फुड कोर्ट भी बनवाया गया है। दो नए गेट का भी निर्माण कराया गया है। भवन निर्माण निगम इसे अब हैंड ओवर करने की तैयारी में है। मेला परिसर में एक पुरुष व एक महिला शौचालय का निर्माण कार्य हुआ है।

आधारभूत संरचनाओं के जरिए बढ़ रही सुविधा

हिजला मेला परिसर का मुख्य द्वार समेत फूलों-झानों कला मंच, मैदान परिसर और सामुदायिक भवन का भी कायाकल्प करने के साथ कई सुविधाएं भी बढ़ाने की पहल हुई है। पर्याप्त रोशनी के लिए हाइमस्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। भवन निर्माण निगम के मुताबिक मेला क्षेत्र में घर हाइमस्ट लगाया गया है। स्थायी तौर पर साउंड सिस्टम और किचन सामग्री की व्यवस्था भी 10 फरवरी तक बहाल होगी।

हिजला मेला परिसर के उन्नयन का कार्य टेंडर के माध्यम से पांच करोड़ 81,29,371 रुपये की लागत से कराया गया है। राशि कल्याण विभाग से उपलब्ध कराया गया है और कार्य भवन निर्माण निगम के जरिए हो रहा है। तमाम आधारभूत संरचना बनकर तैयार है और इसे 10 फरवरी तक अनुमंडल पदाधिकारी को हैंड ओवर करने की तैयारी है।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण निगम
राजकीय जनजातीय हिजला मेला का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस मेला से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पहचान जुड़ी है। झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई प्रदेशों से इस मेला का जुड़ाव वर्षों से कायम है। मेला परिसर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए जाएंगे ताकि यहां आने वाले ग्रामीण व शहरी लोगों को बदलाव का एहसास हो सके। साथ ही मेला की गरिमा व अक्षुण्णता को भी बरकरार रखा जाएगा।



- अभिजीत सिन्हा, उपायुक्त

BRIEF NEWS

झारखंड में ग्रामीण जीवन की रीढ़ बन चुका मनरेगा : मंत्री
RANCHI : मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा झारखंड के ग्रामीण जीवन की रीढ़ बन चुका है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस योजना को एक नई शक्ति प्रदान की है। मनरेगा केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मंत्री बुधवार को रांची में शेयरिंग द एक्सपेरियंस एंड सक्सेस स्टोरी एंड फेलिसिटीटिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग महिला मेटा विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़क, तालाब, कुएं और अन्य स्थायी परियोजनाओं का निर्माण कर गांवों में विकास की मजबूत नींव रखी जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि मनरेगा के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका मिले और पंचायत स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और अधिक हो।

नगर निगम चुनाव में सोच-समझकर करें मतदान : निराला

RANCHI : रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश निराला ने नगर निगम चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं से जागरूक होकर सोच समझकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बुधवार को प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा कि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं की है कि वे यह तय करें कि उनके वार्ड के लिए कौन प्रत्याशी वास्तव में काम कर रहा था और कौन अब केवल चुनाव के समय सक्रिय हुआ है। निराला ने कहा कि वोट देने से पहले बीते वर्षों की जमीनी हकीकत को जरूर याद किया जाना चाहिए। पूरे शहरी क्षेत्र में हल्की बारिश में भी जलजमाव, गर्मी में गंधीर पेयजल संकट, कूड़ा-कचरा का अनियमित उठाव, जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कें आम समस्या बनी हुई हैं।

ठंड बढ़ने के बाद जरूरतमंदों में किया गया कंबल वितरण



RANCHI : तमाड़ प्रखंड के मोदीडीह टोला में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह मुंडा ने किया। वे अखिल भारतीय जनवासी कल्याण केंद्र के प्रांतीय सदस्य भी हैं। इसके अलावा सुदूर जनजातीय बहुल अरहंगा पंचायत क्षेत्र के बुरुहातु और ईचापीड़ी गांव में सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम मुंडा द्वारा भी दर्जनों वृद्धों को कंबल वितरित किए गए। लक्ष्मण सिंह मुंडा ने बताया कि कंबलों की व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ता अनुज कसेरा के सहयोग से की गई।

जनचेतना को जागृत करने में मीडिया की भूमिका अहम : राज्यपाल

PHOTON NEWS RANCHI : मीडिया समाज का सजग प्रहरी है और इसे लोकतंत्र का 'चतुर्थ स्तंभ' कहा जाता है। पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि जनचेतना को जागृत करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण आधार है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यह बात बुधवार को रांची प्रेस क्लब की ओर से रातू स्थित जेके इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी में आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

राज्यपाल ने कहा कि मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं

रांची प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 का हुआ उद्घाटन



कार्यक्रम में भाग लेते राज्यपाल संतोष गंगवार व अन्य

टीम भैरवी और अमानत ने दर्ज की जीत

पहले दिन टीम भैरवी ने टीम कारो को 18 रनों से और टीम अमानत ने टीम अजय को सात विकेट से हराया। पहले मैच में भैरवी ने पहले बॉटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन का स्कोर खड़ा किया। जिसमें विककी पासवान 117, पिटू टुडे 18 का योगदान रहा। जबकि कारो के कुमार सौरव ने 28 रन देकर 2 विकेट लिया। कारो की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी। कारो के अनस रहनुमा ने 68, कुमार सौरव 28 बना सके। वही भैरवी के राजू सिंह 25 रन देकर 2 विकेट लिया। जबकि विककी पासवान ने 31 रन देकर 2 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच विककी पासवान बने। दूसरे मैच में अजय की टीम ने 3 विकेट पर 124 रन का स्कोर खड़ा किया। जिसमें राकेश सिंह 83, पंकज सिंह 22 का योगदान रहा। वही बिपिन पांडेय ने 30 रन देकर 3 विकेट लिया। अमानत की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच जीत लिया। अमानत की ओर से शमीम राजा 52, रियाज आलम 41 रन बनाए। वही अमित कुमार झा 33 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे। प्लेयर ऑफ द मैच शमीम राजा बने।

राज्यपाल ने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद के दौरान भी झारखंड में खेल प्रतिभाओं की असीम संभावनाओं पर चर्चा हुई थी।

राजधानी के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगातार आगजनी की घटनाओं का खुलासा

लोअर बाजार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से एक को किया गिरफ्तार

PHOTON NEWS RANCHI : खादगढ़ा बस स्टैंड पर लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोअर बाजार थाने की पुलिस ने अर्जुन भोक्ता नामक आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से माचिस का डिब्बा और लाइटर बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में आरोपी पर जानबूझकर आग लगाने का शक है। इस संबंध में रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे खादगढ़ा बस स्टैंड पर खड़ी छह बसों में अचानक आग लग गई थी, जिसमें सभी बसें जलकर खाक हो गईं। इस घटना की जांच जारी थी, उसी दौरान 2 फरवरी को बस टर्मिनल के सामने खड़ी सिटी बस में फिर आग लग गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा ली गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में एक संदिग्ध व्यक्ति का हाथ फुटेज में कैद हुआ। फुटेज में देखा गया कि बस में आग लगने से ठीक पहले वह व्यक्ति हाथ में कपड़ा लिए बस में घुसा और बाहर निकलते ही आग भड़क उठी। पुलिस ने आगे जांच की तो 1 फरवरी की घटना वाली पहली जलकर खाक हुई बस के पांच मिन्ट पहले भी यही व्यक्ति उसी बस के पास से गुजरता नजर आया।

प्रारंभिक जांच में आरोपी पर जानबूझकर आग लगाने का है शक

विशेष टीम की छापेमारी के दौरान हुई गिरफ्तारी
इन सुरागों के आधार पर लोअर बाजार थाने में 3 फरवरी को कांड संख्या 31/2026 धारा 326(जी)/327(2) बीएसएफ के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन भोक्ता है, जो रांची के सिकिंदरी का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक माचिस का डिब्बा और एक लाइटर भी बरामद किया गया है।

अत्यधिक नशे में था अर्जुन भोक्ता
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि आरोपी अर्जुन भोक्ता को जिस समय पकड़ा गया वह अत्यधिक नशे में था या तो उसने शराब का नशा किया था या फिर ड्रैगिंग का। सिटी एसपी के अनुसार, इस मामले में दर्जनों लोगों से पूछाछा की गई है। लेकिन अंत में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।



साल 2023 में 9 बसों में लगी थी आग

खादगढ़ा बस स्टैंड में भीषण आग लगी कि यह पहली घटना नहीं है जिसे किसी नशेड़ी या फिर सिरफिरे के द्वारा अज्ञान दिया गया हो। साल 2023 में जून महीने में भी 9 बसों में आग लगी थी। जून महीने में 5 घंटे के अंतराल में खादगढ़ा बस स्टैंड में दो बार भीषण आग लगी थी, इस आग लगी में 8 बसें जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं, जबकि एक बस को अग्निशमन विभाग के द्वारा बचा लिया गया था। 9वें बस में आंशिक रूप से नुकसान हुआ था, लेकिन बाकी आठ बसें तो पूरी तरह से जल कर राख हो गई थीं। पहली वारदात में कुल 5 बसों में अज्ञान आग लगी थी आनन-फानन में दमकल के

थी। एक बार फिर से अग्निशमन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। इस बार भी दमकल के वाहनों को खादगढ़ा बस स्टैंड पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। लेकिन, आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते एक बार फिर से चार बसें जलकर खाक हो गईं। दूसरी बार भी दमकल के 6 वाहनों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। बाद में सीसीटीवी जांच में यह बात सामने आई कि एक नाबालिग द्वारा बसों में स्प्रेट फिडक कर आग लगाई गई थी। इसके बाद आरोपी नाबालिग को पुलिस के द्वारा निरूद्ध किया गया था।

तीन डैमों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट गंभीर, डीसी से रिपोर्ट तलब

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में तीन डैम हैं, जो राजधानीवासियों के पेयजल की जरूरत को पूरा करते हैं। इनके नाम हैं- धुवाँ डैम, कांके डैम और गेतलसूद डैम। लेकिन, तीनों डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण का मामला सामने आने पर झारखंड हाईकोर्ट ने इसे गंभीर बताया है जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। मामले की विस्तृत सुनवाई 26 मार्च को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस सोनक की खंडपीठ में रांची के जलश्रोतों और तीनों प्रमुख डैम के क्षेत्र में अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने रांची के

एन्कोवमेंट हटाने के लिए हो रही कार्रवाई

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर रांची नगर निगम से रिपोर्ट तलब किया है। नगर निगम की ओर से अतिरिक्त एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हरमू नदी, हीनू नदी और धुवाँ डैम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। इस दौरान एफिकस क्यूरी इंडजीति सिन्हा की ओर से बताया गया कि तीनों डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हुआ है।

उपायुक्त से जानना चाहा कि डैमों के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी और उन जमीनों पर कितना अतिक्रमण हुआ है। खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है। शपथ पत्र के जरिए इन सवालों का जवाब मांगा गया है।

संक्रमित ब्लड प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने का आदेश

RANCHI : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस संबंध में दीपक हेंब्रम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही चाईबासा सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि यदि मामले में संज्ञेय अपराध बनता है, तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई।

झारखंड में पछुआ हवा से बड़ी ठंड, तापमान में 3-4 डिग्री गिरावट के दिख रहे आसार

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में उत्तर-पश्चिमी (पछुआ) हवा के प्रभाव से बुधवार को दिनभर ठंड का अहसास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे का कुहासा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। विभाग की ओर से गुरुवार को गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में कहीं-कहीं घने कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले बुधवार को भी राज्य के



उत्तर-पश्चिमी भाग के कुछ इलाकों में घने कुहासे की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया था। कुहासे के कारण सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से

आंशिक बादल छाप रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की गई। वहीं दोपहर में धूप निकलने के कारण हल्की गर्मी का भी अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को रांची में अधिकतम 26.3 और न्यूनतम 13.1 डिग्री, जमशेदपुर में 28.7 और 15.0 डिग्री, डालटेनगंज में 29.6 और 13.1 डिग्री, बोकारो में 28.5 और 13.7 डिग्री, चाईबासा में अधिकतम 30.8 और न्यूनतम 13.2 डिग्री, खुटी में 28.1 और 11.5 डिग्री, लोहरदगा में 25.5 और 10.4 डिग्री, लातेहार में 21.7 और 11.9 डिग्री तथा सरायकेला में 29.1 और 12.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

समस्या न सड़क, न नाली, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं नागरिक

रांची में न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली के लोग परेशान

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 स्थित न्यू विद्यानगर और वार्ड 35 के पहाड़ टोली की हकीकत की पड़ताल की गई, जहां विकास के दावों की पोल खुलती नजर आई। इस इलाके में रहने वाले लोग आज भी सड़क, नाली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, बारिश के मौसम में न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली की हालत और भी भयावह हो जाती है। सड़कों पर जलजमाव इतना बढ़ जाता है कि पानी घरों के भीतर तक घुस जाता है। कई गलियां ऐसी हैं जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि नालियों का या तो

पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है दो किमी आगर बरसात में जलजमाव लोगों की परेशानी है, तो गर्मी के मौसम में पेयजल संकट सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोगों को दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होती। टैंकर भी कभी-कभार ही पहुंचता है, जिससे लोगों को मजबूरी में निजी साधनों से पानी खरीदना पड़ता है।

शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम, वार्ड प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में कोई देखने तक नहीं आता। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हर बार आस्थासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। नाली निर्माण और सड़क सुधार की फाइलें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। लोगों में बढ़ता असंतोष न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली के लोगों का कहना है कि वे सिर्फ बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, पक्की सड़क, सही नाली व्यवस्था और नियमित पेयजल आपूर्ति। लोगों का साफ कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

ज्यादा प्रभावित हैं। एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहन भी कई बार अंदर तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आपात स्थिति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

खाटू धाम निशान यात्रा के लिए 65 सदस्यों का दल हुआ खाना

RANCHI : श्री श्याम मण्डल, रांची का 65 सदस्यों का दल बुधवार को रेल मार्ग से खाटू धाम निशान यात्रा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से खाना खाया। यह दल राजस्थान के सीकर जिला स्थित खाटू नरेशा श्याम बाबा के प्रसिद्ध मंदिर में पवित्र निशान अर्पित करेगा। यह दल शुक्रवार को रींगस से 20 किलोमीटर की पदयात्रा कर श्रद्धापूर्वक खाटू धाम में श्री श्याम प्रभु और श्री हनुमान जी महाराज को निशान अर्पित करेगा। वहीं 8 फरवरी खाटू से प्रस्थान कर सालासर और झुझुनू धाम होते हुए 9 फरवरी को यह दल दिल्ली से प्रातः हवाई मार्ग से रांची पहुंचेगा।

रांची-हटिया से विशेष ट्रेनें चलाने की सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने की मांग

PHOTON NEWS RANCHI : राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने होली पर्व के अवसर पर रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और संभावित असुविधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। यह जानकारी उन्होंने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञापन में दी। डॉ. वर्मा ने पत्र में उल्लेख किया है कि रांची, झारखंड की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, व्यापार और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इन्हीं कारणों से रांची और हटिया से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए

बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, जबकि वर्तमान ट्रेन सेवाएं इस अतिरिक्त दबाव को संभालने में अक्सर असमर्थ रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची, अत्यधिक भीड़ और गंधीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।



समाचार सार

मेयर पद के लिए 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में



JAMSHEDPUR : मानगो में मेयर पद के लिए कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बुधवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पांच उम्मीदवार पहले नामांकन दाखिल कर चुके थे। इस तरह, अब मानगो में मेयर पद के लिए कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जुगसलाई में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बुधवार को आखिरी दिन जुगसलाई में अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। चाकुलिया नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के लिए आज चार उम्मीदवारों ने पत्र भरा है। अब गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच का दिन है। इस दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर किसी के नामांकन में कोई खामी निकलती है, तो उसका पत्रा रद्द कर दिया जाएगा। फिर वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। शुक्रवार को नाम वापसी का दिन है। शुक्रवार को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगा। इसके बाद उम्मीदवार अपने प्रचार में जुट जाएंगे। मानगो में मेयर पद के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बना गुला की पत्नी सुधा गुला और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव के अलावा जेबा कादरी, शबाना बानो, शाइस्ता परवीन उर्फ जेबा खान, वनिता सहाय, राय मुनि सुंडी, काकोली महतो, इंदिरा सुंडी, भाजपा नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह, लकी सिंह, पार्वती देवी, प्रतिभा रानी, सुशील सिंह, अनीता देवी और सोना मुनी सोरेन मेयर पद की उम्मीदवार हैं। जुगसलाई में अध्यक्ष पद के लिए आरती चौधरी, जसप्रीत कौर, नौशीन खान, इंदू देवी, नीलोफर हुसैन, नूतन सिंह, डाली मलिक, मुसंरत खातून, बलबीर कौर, रिंकू सिंह आदि चुनाव मैदान में हैं। चाकुलिया से संध्या रानी सरदार, चंदन मुर्मू, सोमवारी सोरेन और शिलावती टुडू अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो

CHAIBASA : झारखंड के चाईबासा में युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चाईबासा मुफ्तसिल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार के सीतामढ़ी का निवासी 26 वर्षीय मुकेश सिंह है। आरोपी एक कंपनी में तमिलनाडु में काम करता था। वहीं चाईबासा की युवती भी काम करती थी। यहाँ दोनों के बीच जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और उसने युवती से प्रेम का नाटक कर उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसका शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती चाईबासा आ गई। बाद में युवक भी चाईबासा आ गया। इसके बाद युवती को अश्लील वीडियो दिखा कर अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बनाया। बाद में जब युवती ने इनकार किया तो धमकी दी। युवती को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बाद पीड़िता ने चाईबासा मुफ्तसिल थाना में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही आरोपी को चाईबासा से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चाईबासा मुफ्तसिल थाना पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।



पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो

टांडा व पुलिस कर्मी हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

JAMSHEDPUR : मानगो थाना क्षेत्र के न्यू पुरलिया रोड नंबर 16 के पास बदमाशों ने सज्जाद खान उर्फ टांडा की हत्या कर दी थी। घटना को



अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भी हत्यारोपियों ने गोलीयां चलाई थीं। इस घटना में टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो शहीद हो गए थे। घटना में सलिन हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन दो हत्यारोपी फरार चल रहे थे। यह दोनों सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। जिन हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सरायकेला-खरसावां जिले के कांडा थाना क्षेत्र के रियारदा गांव का रहने वाला लुकू माडी उर्फ रोहित माडी और इसी गांव का रहने वाला गणेश मुर्मू शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली छापामार टीम में डीएसपी हेड क्वार्टर वन भोला प्रसाद के अलावा मानगो थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद भी शामिल थे।

आरोप-प्रत्यारोप

मानगो के कचरे को लेकर एक-दूसरे पर हो रहा दोषारोपण, लांघी जा रही भाषा की मर्यादा

नगर निकाय चुनाव के बहाने फिर बज्जा व सरयू आमने-सामने

MUJTABA RIZVI @ JSR :

मानगो में मेयर के चुनाव को लेकर एक बार फिर दो चिर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिज्ञ आमने-सामने हैं। बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मेयर पद पर नामांकन के बाद मामला गरमा गया है। इस बार मुद्दा बना है मानगो की गंदगी, ओल्ड पुरलिया रोड और पेयजल की दिक्कत। इसे लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप के दौरान भाषा की मर्यादा भी लांघी जा रही है। सारी समस्याओं के लिए विधायक सरयू राय बन्ना गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो बन्ना गुप्ता का कहना है कि वर्तमान में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय हैं। अब उन्हें हर समस्या का हल



निकालना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि, उन्होंने सारी समस्या हल कराने का वादा करने के बाद ही लोगों के वोट हासिल किए थे। ओल्ड पुरलिया रोड पर धमासान : ताजा विवाद ओल्ड पुरलिया रोड की जर्जर स्थिति से शुरू हुआ है। इसके बारे में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बयान दिया था कि उन्होंने मानगो के लाइफ लाइन कही जाने वाली ओल्ड और न्यू पुरलिया रोड का निर्माण कराया



था। अपने कार्यकाल में इन दोनों सड़कों की मरम्मत भी कराई थी। अब ओल्ड पुरलिया रोड जर्जर हो रही है तो वर्तमान विधायक सरयू राय इसके लिए दोषी हैं। उन्हें इस सड़क की मरम्मत करानी चाहिए। इसका जवाब विधायक सरयू राय ने दिया और जनता को जानकारी दी कि ओल्ड पुरलिया रोड की मरम्मत के लिए उन्होंने पथ निर्माण विभाग से बात की है। इसकी फाइल रांची में लॉबिंग है।

मेयर के चुनाव पर टिकी राजनीति

इसका जवाब देते हुए विधायक सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर किसी तरह जोड़ोड़ कर मेयर पति बनने ही हसरत पालन का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि बन्ना गुप्ता बेशर्मी के साथ मेयर पति बनने के लिए बेकरार हैं। अब बन्ना गुप्ता ने इसका जवाब दिया और कहा कि इसमें बेशर्मी की क्या बात है। सुधा गुप्ता उनकी पत्नी हैं। उन्होंने सुधा गुप्ता की मांग में सिंदूर डाला है। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने बड़ी चालाकी से रामारवां पूजा का भी जिक्र किया और सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि मेयर पद पर मानगो का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। यह सर्वैधानिक अधिकार है। सुधा गुप्ता मेयर बननेगी तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि संस्कार तो उन्हें यह नहीं सिखाते।

गंदगी को लेकर राजनीतिक चक्रव्यूह

साथ ही बन्ना गुप्ता ने पलटवार करते हुए मानगो में गंदगी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरयू राय पर आरोप लगाया कि सोनारी में जहां मानगो का कचरा डंप होता था, वहां टाटा स्टील को लाभ पहुंचाने के लिए कचरा डंपिंग रुकवा दी। इसी का नतीजा है कि कचरा डंपिंग कहां हो यह नगर निगम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी के चलते मानगो की गलियों को पर कचरा डंप हो रहा है। अब विधायक सरयू राय ने बन्ना के इस आरोप का जवाब दिया है। सरयू राय ने कहा है कि सोनारी में कचरा डंप करने पर रोक उसी सरकार ने लगाई है जिस सरकार में बन्ना गुप्ता मंत्री थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो नगर निगम और जेएनएसपी का कचरा बहुत दिनों से सोनारी में मरीन ड्राइव किनारे टाटा स्टील के भूखंड पर फेंका जा रहा था। वहां कचरे का पहाड़ बन गया था। इसमें आग लग गई थी। आसपास के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर समस्या बताई। समाधान नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया गया। एनजीटी ने आदेश दिया कि मरीन ड्राइव किनारे कचरा फेंकना बंद की जाए। आग बुझाए और कचरे का पहाड़ हटाए। इसके बाद उसी सरकार ने वहां कचरा फेंकना बंद कराया जिस सरकार में बन्ना गुप्ता मंत्री थे। कचरा हटाने के लिए कई करोड़ का टेंडर निकाला गया। सरयू ने सवाल किया कि अब जनता बताए मानगो में गंदगी का दोषी कौन है।

बीजेपी लड़ेगी मानगो नगर निगम में मेयर चुनाव

मानगो में मेयर की सीट पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी। शायद रांची में यह फैसला हुआ है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय चाहते थे कि मानगो नगर निगम में मेयर का चुनाव जदयू लड़े। इसे लेकर सरयू राय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से बात की थी। मगर, भाजपा ने उनकी बात नहीं मानी है। अब भाजपा नेता नीरज सिंह की पत्नी ही मानगो नगर निगम के मेयर पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार होंगी। जदयू भी इसके लिए तैयार हो गया है।

दंतैल हाथी ने गांवों में मचाया उत्पात, 12 मकान क्षतिग्रस्त

गजराज को पकड़ने में नाकाम रहा वन विभाग, इलाके में दहशत

● आधा दर्जन गांवों में घूमता रहा हाथी, आधी रात में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार व मशाल ले खेदड़कर भगाया



प्रतीकालोक तहवीर

आतंक फैलाया और रात दो बजे तक क्षेत्र में घूमता रहा। आधी रात गांव में घुसा हाथी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के तेंदूडी पोसी निवासी ग्रामीण डाकवा वीरेंद्र बालमुचू ने बताया कि हाथी ने रात

करीब 12 बजे बूढ़ा खमण जंगल की ओर से निकलकर डौडगुवा, चिंगली, बाइहातु, कूदाहातु, सोसोपी, तेंदूडी पोसी, जोड़ापोखर तथा कुंडुओर गांवों में विचरण किया।

माफिया पर प्रशासन की मार 2500 सीएफटी अवैध बालू जब्त

CHAKRADHARPUR :

जिला प्रशासन और अवैध तरीके से बालू का खनन व ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहता है। प्रशासनिक कार्रवाई में अक्सर अवैध बालू की बरामदगी होती थी लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आते थे। प्रशासन की ओर से इस अवैध काले कारोबार को बंद करने के लिए समय-समय पर योजनाबद्ध तरीके से अभियान भी चलाया जाता रहा है। इस कार्रवाई में तीन हाईवा और दो डंपर जब्त किए गए। इन पांचों वाहनों में लगभग 2500 सीएफटी अवैध बालू लदा हुआ था। सभी जब्त वाहनों को चक्रधरपुर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित विभाग को सौंपते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



जब्त किया गया डंपर

अवैध रूप से बालू ढो रहे पांच भारी वाहन पकड़े गए। चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट श्रुति राज लक्ष्मी ने सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तीन हाईवा और दो डंपर जब्त किए गए। इन पांचों वाहनों में लगभग 2500 सीएफटी अवैध बालू लदा हुआ था। सभी जब्त वाहनों को चक्रधरपुर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित विभाग को सौंपते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

PHOTON NEWS CHAIBASA :

पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के माउंट कामेल इंग्लिश मीडियम विद्यालय, रूगुइसाई के छात्रावास से लापता हुए दो नाबालिग छात्रों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। माउंट कामेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुमारडुंगी के पोखरिया गांव का छठी कक्षा के छात्र इराज पिंगुवा (उम्र करीब 12 वर्ष), पिता अनन्त पिंगुवा व कक्षा सातवीं के छात्र समीर जेराई (उम्र करीब 13 वर्ष), पिता लेवा जेराई, ग्राम झीरपाई टोला-बाईहातु, थाना जगन्नाथपुर से दो फरवरी को दोपहर करीब 12.30 बजे छात्रावास से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बच्चों



बरामदगी की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

● फोटोन न्यूज

एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम को मिली सफलता

छात्रों के लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को दी गई। पुलिस अधीक्षक अमित रेनु के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने जांच के क्रम में चार फरवरी को डंगुवापोसी रेलवे स्टेशन के पास से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया।

के न मिलने पर दोनों छात्रों के अभिभावकों की ओर से जगन्नाथपुर थाने में लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन के

जगन्नाथपुर थाने में लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन के

डायन-बिसाही के आरोप में वृद्धा की पीट-पीट कर हत्या

CHAIBASA :

पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। ग्रामीणों ने एक चुनगु महिला को डायन-बिसाही के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला। वृद्धा को पत्थर से भी कूचा गया। मृतक महिला 57 वर्षीय पदनी सुरीन है। घटना बीते मंगलवार रात की है। हालांकि हत्या के 12 घंटे बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस इस संबंध में कुछ भी बोलने से करारा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल को चला रही है। सवाल यह है कि आखिर हत्या किस कारण से की गई है। चर्चा है कि वृद्धा की हत्या डायन-बिसाही के आरोप में की गई है। बहरहाल क्षेत्र के लोग कुछ भी



बताने से डर रहे हैं। गांव के लोग भी पलायन कर चुके हैं। महिला को पहले पीटा फिर पत्थर से कूचा पदनी सुरीन कि हत्या के बाद शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीणों ने वृद्धा को डंडे और ईंट-पत्थर से मारा है। इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला किया गया। लोगों ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।

परिजनों ने पुलिस का जताया आभार

पिछले कई दिनों से छात्रों के परिजन व रिश्तेदार काफी तनाव में थे। उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका बढ़ रही थी। पुलिस की ओर से बरामद किए जाने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

आधार पर थाने में तीन फरवरी को मामला दर्ज किया गया।



मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण से लग रहा जाम, हदसे का खतरा

GHATSILA : शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण अब एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप फुलडुंगरी मुख्य सड़क से लेकर गोपालपुर ओवरब्रिज, सुभाष चौक, बीओआई मोड़, पोस्ट ऑफिस मोड़ और काशिदा क्षेत्र तक सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाई गई अस्थायी दुकानों और खड़े वाहनों ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। हर दिन यहां लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। इससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के पास फुलडुंगरी मुख्य सड़क पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अनमोल जीवन नर्सिंग होम से लेकर वन विभाग कार्यालय के समीप तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें सजी हैं। इसके साथ ही सड़क किनारे बिना किसी नियम के बाइक, ऑटो और अन्य वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क पहले से ही जकड़नी हो गई है परिणामस्वरूप यहां हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है और आम लोगों के साथ-साथ मरीजों, स्कूली बच्चों और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाक सामने आ जाने वाले वाहन, दुकानों की भीड़ और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। घाटशिला की मुख्य सड़क गोपालपुर ओवरब्रिज से लेकर सुभाष चौक तक अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है। बीओआई मोड़ से पोस्ट ऑफिस मोड़ तक भी सड़क पर जगह-जगह अतिक्रमण है। इससे दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों को फिकलने में काफी दिक्कत होती है। सुहृद और शाम के समय यहां स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब कार्यालय, बाजार और स्कूल की आवाजाही एक साथ होती है। काशिदा क्षेत्र में पुराना अनुमंडल अस्पताल चौक और रेलवे अंडरपास के पास भी अस्थायी दुकानों ने सड़क को जकड़ लिया है। यहां एल्ट्रेस, मालवाहक वाहन और आम लोगों की गाड़ियां एक-दूसरे को फंस जाती हैं। कई बार मरीजों को ले जा रही एल्ट्रेस भी जाम में फंस गई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

BRIEF NEWS

पुलिस ने 20 हजार के इनामी डकैत को किया गिरफ्तार

EAST CHAMPARAN :

एसटीएफ और डीआईओ की संयुक्त टीम ने 20 हजार रुपये के इनामी डकैत मिथुन राम को गिरफ्तार किया है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जागपाकड़ गांव निवासी मिथुन राम लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मिथुन राम पर जिले के विभिन्न थानों में डकैती सहित कई गंभीर आपराधिक मामलों दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और उस पर 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लंबे समय से फरार डकैत मिथुन राम अपने पैतृक गांव जागपाकड़ में है। सूचना की पुष्टि के बाद एसटीएफ और डीआईओ की टीम को अलर्ट किया गया। एक विशेष रणनीति के तहत छापेमारी कर पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य अपराध साक्ष्यों के बारे में पूछताछ कर रही है।

रोहतास डेयरी में पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

DEHRI-ON-SONE :

गाय व भैस की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और व्यवहार को समझना और उन्हें उचित तरीके से संभालना व कम लागत में ज्यादा दूध उत्पादन का उत्पादन किया जा सकता है। रोहतास डेयरी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आनंद अमित ने प्रशिक्षण को आगे पशुपालकों को सम्बोधित करते उक्त बातें आज कही। उन्होंने बताया कि शाहाबाद के चारों जिलों रोहतास, भोजपुर, बक्सर व कैमूर के के 480 पशुपालकों को पशु प्रबंधन के प्रशिक्षण दिया गया। आज से 780 को प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ है। जो तीन माह तक चलेगा। एक बैच में 36 पशुपालकों को तीन दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण में डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य, चारा प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण, और पशुपालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है।

अवैध बालू खनन पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, 6 वाहन जब्त

SARAN :

जिला प्रशासन सारण ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव के नेतृत्व में तीन फरवरी की मध्य रात्रि को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन छापेमारी की गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान दरहरा थानांतर्गत बिना वैध परिवहन चालान के बालू ले जा रहे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। इन सभी वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कुल 5.30 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया गया।

कार्यक्रम

'सात निश्चय-3' के तहत शिक्षा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी नई उड़ान

213 प्रखंडों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज इसी साल जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'सात निश्चय-3' के चौथे निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्वल भविष्य' के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्रों, विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। वर्तमान में राज्य के कुल 534 प्रखंडों में से 213 प्रखंड एक्स हैं, जहां कोई भी अंगीभूत या संबद्ध डिग्री कॉलेज नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए प्रथम चरण में इन सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने तथा जुलाई 2026 तक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के पुराने एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत कुल 55 शिक्षण संस्थानों का



चयन किया गया है। इन संस्थानों के उन्नयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन संस्थानों के अनुभवों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से विमर्श कर उनके

सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना से खासकर लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा,

प्रदेश में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे सृजित : सम्राट चौधरी

बिहार में रक्षा गलियारा (डिफेंस कॉरिडोर) के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय की अध्यक्ष टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में प्रस्तावित रक्षा गलियारा की योजनाओं, संभावनाओं और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान बिहार के उम्मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रक्षा गलियारा न केवल राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि यह बैठक पटना स्थित उनके आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्रालय की ओर से अध्यक्ष दौरे पर आए राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (एनडीए) के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पहल राज्य के औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके अलावा राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना और भागलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि रक्षा गलियारा के निर्माण से बिहार रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य को उद्योग और रोजगार का हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अध्यक्ष टीम के साथ हुई यह बैठक इसी दिशा में एक ठोस पहल है।

जिससे उनकी सहभागिता और बढ़ेगी। वहीं, प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने से युवाओं को रोजगारपरक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी और इन संस्थानों का

गौरव पुनः स्थापित होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह पहल राज्य के चहुँमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाएगी।

सारण पुलिस ने विशेष अभियान में 21 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

सारण : पुलिस ने अपराधियों और शराब माफियाओं के खिलाफ अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चिनीत कुमार के निर्देश पर चलाए गए 24 घंटे के विशेष अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान 9 चारिटीयों सहित कुल 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सारण में नौ अभियुक्त, शराब का सेवन में सात, शराब कारोबार में तीन, आर्म्स एक्ट में एक और अन्य मामलों में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से की गई छापेमारी में पुलिस ने कुल 262.755 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसमें 120 लीटर देशी और 142.755 लीटर विदेशी शराब शामिल है।

'पुलिस मित्र' की नौकरी के नाम पर 42 युवाओं से टगी

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से बेरोजगार युवकों से टगी का मामला सामने आया है। टगी ने बेरोजगार युवकों को 'पुलिस मित्र' बनाने का झंसा देकर लाखों रुपये पेंडेंट लिए हैं। इससे बड़ी बात यह है कि टगी का यह खेल पुलिस और थाना के परिसरों में खेला गया और पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

हालांकि मामला सामने आने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टगी के इस पूरे खेल में शामिल शान्ति के खुलासे के लिए प्रशिखु आईपीएस हेमंत सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। इस संबंध में टगी का शिकार कोटवा थाने के कोइरगावा निवासी रवि कुमार यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि जून 2025 में चार युवक उसके पास पहुंचे थे और



टगी के शिकार बेरोजगार युवक

उसे पुलिस मित्र की नौकरी दिलाने और संस्था में जिला कोऑर्डिनेटर का पद दिलाने के नाम पर अपनी बातों में फंसा कर 4 लाख की टगी कर लिए। रवि ने ऑनलाइन कैश ट्रांसफर का प्रूफ पुलिस को दिया है। इसके साथ ही उक्त गैंग ने उसे आई कार्ड देकर कोटवा में ही जर्दनिंग भी करा दिया। उसे कहा गया कि आप अन्य युवकों को भी इस नौकरी के लिए लेकर आइए आपको बकायदा तनखाह दिया जाएगा। इतना ही नहीं शान्ति टगी

ने खुद को प्रभावशाली बताकर मोतिहारी और आसपास के इलाकों के करीब 42 युवकों को पुलिस मित्र के रूप में बहाली का लालच दिया। टगी ने दावा किया कि उन्हें पुलिस विभाग से जोड़ा जाएगा और हर महीने 16 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। शांति टगी ने युवकों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें डीजीपी के नाम लिखा गया एक पत्र दिखाया, जिस पर रिसीविंग होने का भी दावा किया गया। इसके बाद

युवकों को अलग-अलग थानों के पुलिस मित्र बनाकर थाना परिसर में बकायदा आई-कार्ड भी पहनाया। मिली जानकारी के अनुसार इस गोरखधंधे को लेकर अरेराज की महिला थानाध्यक्ष पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक रिटायर्ड चौकीदार के बेटे को इस बहाली के लिए तैयार किया। बताया जा रहा है कि अरेराज थाना से सेवानिवृत्त तीन चौकीदारों के बेटों से 20-20 हजार रुपये लिए गए, जबकि कुल 60 हजार रुपये प्रति युवक से मांग की गई थी। शेष राशि वेतन शुरू होने के बाद देने की बात कही गई। पीड़ितों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में थानाध्यक्ष ने सहमति जताई थी। शांति टगी ने युवकों को यह खेल महज अरेराज में ही नहीं, बल्कि जिले के कोटवा, घोड़ासहन, पलनवा और गोविंदगंज के युवकों के साथ भी खेला।

डीएम ने किया खनुआ नाला व शहर के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण

सारण : शहर को जलजमाव की स्थायी समस्या से निजात दिलाने और ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने प्रशासनिक अमले के साथ शहर के विभिन्न जल निकासी केंद्रों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने खनुआ नाला सहित शहर के सभी छोटे-बड़े नालों और उनके आउटलेट्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल निकासी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने उप साहवा बंधू सुधाकर सरदार और अंचलाधिकारी सरदार को निर्देशित किया कि साढ़ा ढाला ओवरब्रिज के नीचे से जटही पोखरा, दुधिया पोखरा होते हुए नदी तक तथा दुधिया पोखरा से बन्धी नाला तक के सभी नालों की मापी सुनिश्चित करें।

नवादा के मेडिकल प्रैक्टिशनर अशोक मिस्त्री हत्याकांड में तीन साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार

PHOTON NEWS NAVADA :

नवादा रोह थाना क्षेत्र के कोशीरुखी पंचायत अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर अशोक मिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान बुधवार को एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद मृतक के बैंक खाते से करीब 90 हजार रुपये की निकासी की गई थी। इस वित्तीय लेन-देन की कड़की जोड़ते हुए पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर अपराध से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि, हत्या को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर



पकड़े गए अपराधी व पुलिसकर्मी

कार्रवाई करते हुए तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नारदीगंज थाना क्षेत्र के कुश्वा गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार , नालन्दा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र के मायापुर गांव निवासी रोहित कुमार और नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के लालबीचा गांव निवासी शिवम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है

कि तीनों युवक पहले भी साइबर अपराध की गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। हालांकि, अब तक हत्या में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस इस बिंदु पर गहन जांच कर रही है कि बैंक खाते से निकासी सुनिश्चित साजिश का हिस्सा थी या फिर हत्या के बाद मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया।

बक्सर में मार्च तक तैयार हो जाएगा भार्गव ऋषि आश्रम का तालाब

AGENCY BUXAR :

बक्सर जिले के प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव स्थल भधुअर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहां स्थित भार्गव ऋषि आश्रम का विशाल तालाब आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसका वर्तमान में जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। मान्यता है कि त्रेता युग में यहां भार्गव ऋषि का आश्रम था और पंचकोशी परिक्रमा के दौरान भगवान श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ यहां पहुंचे थे। ऋषि के आग्रह पर लक्ष्मण जी ने अपने बाण से इस तालाब का निर्माण किया था। तभी से यहां प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता आ रहा है। समय के साथ तालाब का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा था, जिसे



देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी साहिला द्वारा भधुअर तालाब का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को मार्च माह तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने तालाब क्षेत्र को श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शौचालय, पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भागलपुर में राष्ट्रीय एकता शिविर शुरू, देशभर से जुटे स्वयंसेवक

युवाओं में सेवा भावना को मजबूत करना एनएसएस का उद्देश्य

AGENCY BHAGALPUR :

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर-2026 का शुभारंभ बुधवार को मारवाड़ी कॉलेज, परिसर में हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए एनएसएस स्वयंसेवक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सेवा भावना को मजबूत करना है। आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में, एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय बिहार-झारखंड तथा त्रिकलमांडवी भागलपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है।



उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों ने स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि एनएसएस युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने वाला एक

सशक्त मंच है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों के लिए विविध शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इनमें स्वच्छता जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण संरक्षण

कार्यक्रम, समूह चर्चा, योग एवं फिटनेस सत्र, व्यक्तिगत विकास कार्यशाला तथा देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक संध्याएं शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने

का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार, राष्ट्रीय एकता शिविर युवाओं को 'विविधता में एकता' के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। अलग-अलग राज्यों से आए स्वयंसेवक अपनी भाषा, वेशभूषा, लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे, जिससे परस्पर समझ, सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह सांस्कृतिक संवाद देश की एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रशासन के प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वयंसेवकों के उत्साह, अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की।

रसूलपुर में बनेगा फुट ओवर ब्रिज, प्रक्रिया शुरू

KATIHAR :

कटिहार संसदीय क्षेत्र के एनएच-131ए पर रसूलपुर के पास नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सांसद तारिक अनवर ने भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर फुट ओवर ब्रिज (रैम्प सहित) के निर्माण की मांग की थी। कटिहार जिला काग्रिस पार्टी के प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुवाला ने बताया कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए मंत्रालय द्वारा इस मांग पर सकारात्मक विचार किया गया है। क्षेत्र में स्कूल, मंदिर, मस्जिद एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के कारण शरीर पैदल आवागमन को देखते हुए प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

कागजी सम्मान की चमक में खोता वास्तविक योगदान

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्र के आत्ममंथन के अवसर भी होते हैं। इन दिनों प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले प्रशंसा पत्रों को समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य यह होता है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र, समाज और व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। किंतु, बीते कुछ वर्षों में इन प्रशंसा पत्रों की प्रक्रिया और चयन पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सबसे बुनियादी सवाल यही है कि क्या किसी प्रशंसा पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक होना चाहिए। यदि हां, तो क्यों। सम्मान तो वह होता है, जो स्वतः मिले, जिसे समाज और व्यवस्था स्वयं पहचानें। यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए स्वयं आवेदन करना पड़े या किसी माध्यम से अपना नाम अनुशंसित करवाना पड़े तो ऐसे सम्मान की नैतिकता और प्रामाणिकता पर स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न होता है। विडंबना यह है कि जब किसी क्षेत्र में अनियमितता, भ्रष्टाचार या अव्यवस्था की खबरें समाचार पत्रों, टीवी चैनलों या सोशल मीडिया पर आती हैं तो प्रशासन तत्काल सक्रिय हो जाता है। जांच बिठा दी जाती है, नोटिस जारी होते हैं और कार्रवाई की घोषणाएं की जाती हैं। यानी नकारात्मक घटनाओं पर प्रशासन की दृष्टि अत्यंत सजग और तीक्ष्ण है। फिर सकारात्मक, रचनात्मक और जनहितकारी कार्यों को पहचानने में वही प्रशासन इतना असाहाय क्यों दिखाई देता है। क्या अच्छे कार्यों को देखने और समझने की प्रशासनिक दृष्टि अब केवल फाइलों और औपचारिक रिपोर्टों तक सीमित होकर रह गई है। वास्तविकता यह है कि आज प्रशंसा पत्रों की व्यवस्था योग्यता की बजाय प्रक्रिया आधारित होती जा रही है। आवेदन, अनुसंधान, विभागीय चैनल और व्यक्तिगत संपर्क- ये सभी सम्मान प्राप्त करने के अनौपचारिक मानदंड बन चुके हैं। परिणामस्वरूप वही लोग बार-बार सम्मानित होते दिखाई देते हैं, जो व्यवस्था के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जानते हैं, न कि वे जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए जमीन पर काम किया है। यह स्थिति सम्मान को प्रेरणा के साधन से अधिक एक औपचारिक रस्म में बदल देती है। यह भी देखने में आता है कि कई बार प्रशंसा पत्र सरकारी कर्मचारियों को उनके नियमित दायित्वों के निर्वहन के लिए दे दिए जाते हैं, जबकि उनका कार्य मूलतः उनकी नौकरी का हिस्सा होता है। इसके विपरीत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग, जो बिना किसी पद या संसाधन के समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे होते हैं, प्रशासन की दृष्टि से बाहर ही रह जाते हैं। क्या यह सम्मान की सही कसौटी है। प्रशंसा पत्रों के मूल्य पर भी विचार आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर पत्र लिखे जाते हैं, वे केवल औपचारिक सम्मान नहीं होते। ऐसे पत्र व्यक्ति के कृतित्व के ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। वे शोध ग्रंथों में उद्धृत होते हैं, सामाजिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इसके विपरीत आवेदन आधारित प्रशंसा पत्र अक्सर समारोह समाप्त होते ही अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। सम्मान की सबसे बड़ी कसौटी प्रशासन नहीं बल्कि समाज होता है। पाठक, दर्शक, श्रोता और आम लोग तब करते हैं कि कौन उनके विश्वास पर खरा उतरा और कौन नहीं। साहित्य और कला के क्षेत्र में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। किसी रचनाकार का मूल्यांकन उसके प्रमाण पत्रों से नहीं, बल्कि उसकी रचनाओं, विचारों और सामाजिक प्रभाव से होता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी औपचारिक सम्मान के भी कुछ लोग समाज में अमर हो जाते हैं, जबकि अनेक पदक और प्रमाण पत्र पाने वाले लोग समय के साथ धुला दिए जाते हैं। यहाँ पद और प्रतिष्ठा के अंतर को समझना भी आवश्यक है। पद से मिलने वाला सम्मान अस्थायी होता है। जब तब व्यक्ति पद पर होता है, तब तक उसके चारों ओर अभिमान और औपचारिक सम्मान की भीड़ रहती है। जैसे ही पद समाप्त होता है या व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, वही भीड़ छुटने लगती है। इसके विपरीत, जो लोग अपने कार्य और कृतित्व के बल पर पहचान बनाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पद से परे होती है और समय के साथ और गहरी होती जाती है। दुर्भाग्य से कुछ अधिकारी पद के मद में यह भूल जाते हैं कि वे राष्ट्र और समाज से बड़े नहीं हैं। पद उन्हें अधिकार देता है, श्रेष्ठता नहीं। यदि किसी अधिकारी ने अपने सेवाकाल में राष्ट्र और समाज के लिए कुछ विशिष्ट नहीं किया, तो ऊंचे पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका जीवन सामान्य ही रह जाता है। इतिहास में अधिकारी नहीं बल्कि विचार, कृतियाँ और योगदान दर्ज होते हैं। यह भी सच है कि साहित्य और कला की समझ न रखने वाले कुछ अधिकारी सम्मान की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में चयन का आधार गुणवत्ता नहीं, बल्कि सुविधा और औपचारिकता बन जाता है। इससे न केवल वास्तविक योगदान करने वालों के साथ अन्याय होता है, बल्कि सम्मान को विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

ANALYSIS



उमाशंकर पांडेय

जल का विषय राज्य सरकारों के दायरे में आता है, मगर केंद्र सरकार विशेष रूप से जल शक्ति मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से देश भर में दीर्घकालिक भूजल प्रबंधन को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। दरअसल भूजल को समझना जरूरी है। भूजल वह मीठा पानी है, जो मिट्टी और चट्टानों में रिसकर भूमिगत यानी भूमि के अंदर संग्रहित हो जाता है, जहां से यह स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। यह नदियों और धाराओं के जलस्तर को बनाए रखता है तथा आर्द्रभूमि में पौधों और जंतुओं के आवास को मजबूती से प्रभावित करता है। भूमिगत परत जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूजल संग्रहित और संचालित हो सके, उसे जलभूत कहा जाता है। जलभूतों से पानी स्वाभाविक रूप से बहकर झरनों, धाराओं और नदियों में योगदान दे सकता है या खुदवाँ वाले कुओं, ट्यूबवेल और बोरवेल के माध्यम से पंप किया जा सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि भूजल प्रबंधन एकूणतः जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण का हिस्सा है। भूजल प्रबंधन के मूल आधार हैं- भूजल (जलभूत) के कार्य और उपयोग, उन पर कार्यरत समस्याएं और दबाव (खतरें) तथा प्रबंधन और स्थिरता पर प्रभाव।

वैश्विक जल संकट के बीच भारत में अशांता का नया संचार हुआ है। पानी खासतौर पर भूजल के संरक्षण के प्रयास निश्चित तौर पर अच्छे संकेत दे रहे हैं। भूजल के अंतर्गत पृथ्वी का कुल 99 प्रतिशत तरल मीठा पानी समाहित है। यह हमें तथ्य तरह के सामाजिक, आर्थिक कठौत पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। इसमें जलवायु लचीलापन भी शामिल है। देश में भूजल कृषि गतिविधियों और पेयजल आपूर्ति का प्राथमिक आधार है। यह लगभग 62 प्रतिशत सिंचाई आवश्यकता, 85 प्रतिशत ग्रामीण खपत और 50 प्रतिशत शहरी मांग को पूरा करता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि गहनता, औद्योगिक विस्तार, और शहरीकरण ने देश में सामूहिक रूप से भूजल प्रणालियों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसलिए सतत भूजल प्रबंधन प्रथा को अपनाया अनिवार्य हो गया है। जल का विषय राज्य सरकारों के दायरे में आता है, मगर केंद्र सरकार विशेष रूप से जल शक्ति मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से देश भर में दीर्घकालिक भूजल प्रबंधन को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। दरअसल भूजल को समझना जरूरी है। भूजल वह मीठा पानी है, जो मिट्टी और चट्टानों में रिसकर भूमिगत यानी भूमि के अंदर संग्रहित हो जाता है, जहां से यह स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। यह नदियों और धाराओं के जलस्तर को बनाए रखता है तथा आर्द्रभूमि में पौधों और जंतुओं के आवास को मजबूती से प्रभावित करता है। भूमिगत परत जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूजल



संग्रहीत और संचालित हो सके, उसे जलभूत कहा जाता है। जलभूतों से पानी स्वाभाविक रूप से बहकर झरनों, धाराओं और नदियों में योगदान दे सकता है या खुदवाँ वाले कुओं, ट्यूबवेल और बोरवेल के माध्यम से पंप किया जा सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि भूजल प्रबंधन एकूणतः जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण का हिस्सा है। भूजल प्रबंधन के मूल आधार हैं- भूजल (जलभूत) के कार्य और उपयोग, उन पर कार्यरत समस्याएं और दबाव (खतरें) तथा प्रबंधन उपयोगों का भूजल प्रणाली की समग्र कार्यप्रणाली और स्थिरता पर प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, भूजल संसाधनों के सतत एवं संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी भूजल प्रबंधन में 4 प्रमुख प्राथमिकताएं आवश्यक हैं। देश में व्यापक भूजल भंडार हैं, जिनकी भौतिक विशेषता और उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न है। फिर भी हाल के दशकों में इन संसाधनों पर अत्यधिक निकासी, घटती गुणवत्ता और सीमित

नियमन से तनाव बढ़ा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। भूजल प्रणालियों पर बढ़ता दबाव तीव्र और मुख्यतः अनियमित पापिंग से देश के कई हिस्सों में जलस्तर में तेजी से गिरावट आई है। यह तथ्य भूमिगत स्रोतों पर हमारी बढ़ती निर्भरता को भी दर्शाता है। इससे जल गुणवत्ता का ह्रास होना स्वाभाविक है। खनन गतिविधियों, औद्योगिक अपशिष्टों और कृषि प्रथाओं से उत्पन्न प्रदूषण साथ ही आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे प्राकृतिक तत्वों ने क्रमिक रूप से भूजल गुणवत्ता को प्रभावित किया है। यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। अनियंत्रित निकासी भी इसके कारक हैं। बढ़ते भूजल तनाव और सतत जल सुरक्षा की जरूरत के जवाब में केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को मजबूत करने, पुनर्भरण व संरक्षण को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक आकलन में सुधार लाने तथा पूरे भारत में सहभागी एवं परिणामोन्मुखी भूजल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाली व्यापक नीतियों, कार्यक्रमों एवं समुदाय-

प्रेरित पहलों का समूह शुरू किया है। इनमें मॉडल भूजल (विकास एवं प्रबंधन) का नियमन और नियंत्रण विधेयक प्रमुख है। इस मॉडल विधेयक को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इनमें से 21 ने इसे अपनाया है। इनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सक्रिय रूप से राज्य सरकारों के साथ संवाद करता है ताकि भूजल संसाधनों का विवेकपूर्ण नियमन एवं सतत प्रबंधन हो। कैच द रेन भी प्रमुख है। इस अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई। यह अभियान जल संरक्षण पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता निर्माण एवं सामूहिक कार्रवाई को हर बूट गिनती का संदेश मजबूत करते हुए प्रोत्साहित करता है। यह देशभर के नागरिकों को व्यावहारिक उपायों एवं समुदाय स्तरीय सहभागिता से भारत के जल भविष्य के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, सभी जल निकायों की

पहचान, जियो-टैगिंग एवं सूचीबद्धता, साथ ही जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, केंद्रित वनीकरण और जागरूकता सृजन पर जोर दिया जाता है। साथ ही निष्क्रिय बोरवेलों का पुनर्जीवन भी किया जा रहा है। यह भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देता है। जल संचयन पहल भीगीदारी पहल को इसमें समाहित किया गया है। यह अभियान 06 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। अटल भूजल योजना (अटल जल) सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय-नेतृत्व वाले सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई यह योजना जल जीवन मिशन के लिए जल स्रोतों की स्थिरता का समर्थन करती है। यह किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी लक्ष्य का भी समर्थन करती है तथा समुदायों में जिम्मेदार जल उपयोग को प्रोत्साहित करती है। यह जागरूकता सृजन, स्थानीय क्षमता निर्माण, अन्य सरकारी योजनाओं से समन्वय तथा उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। यही नहीं 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया मिशन अमृत शरोवर देश के सभी जिलों में अमृत सरोवरों (तालाबों) के निर्माण का समर्थन करता है। प्रत्येक तालाब का न्यूनतम शरोवर एक एकड़ (0.4 हेक्टेयर) तथा जल संग्रहण क्षमता लगभग 10 हजार घन मीटर निर्धारित है।

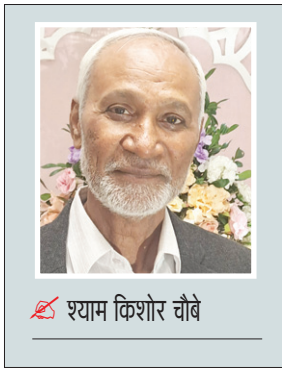
बाअदब होशियार, आ रही शहर की सरकार

इस महीने के आखिरी दिन के ऐन पहले 27 फरवरी को झारखंड के कुल जमा 48 शहरों-कस्बों की सरकारों को ले आने का डिहोरा-वादन हो चुका है। यह कर्मकांड राज्य बनने के 25 वर्षों में चौथी मंतावा होगा। नगर निकायों का गठन पहली मंतावा 2008 में हुआ था, फिर 2013 में और 2018 में भी हुआ था। बीच के तकरौबन दो साल का गैप रहा। प्रस्तावित चुनावों के दायरे में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायतों और कुल मिलाकर 1,087 वार्ड शामिल हैं। इतने ही वार्ड पार्षदों के अलावा निकायों के मेयर/अध्यक्ष का निर्वाचन 43,33,574 वोटर करेंगे। इन वोटरों में 22,07,203 पुरुष और 21,26,227 महिलाओं के अलावा 144 थर्ड जेंडर हैं। चुनावों में खड़े उम्मीदवार सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिए अधिकतम एक लाख रुपये, जबकि सबसे बड़ी इकाई नगर निगम के मेयर पद के लिए आबादी के अनुसार 15/25 लाख और निगम का वार्ड पार्षद बनने के लिए 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर निगमों के

डिप्टी मेयर, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के उपाध्यक्षों का चुनाव परोक्ष रूप से होगा। इन महानुभावों का निर्वाचन विजयी वार्ड पार्षद करेंगे। डिप्टी मेयर और उपाध्यक्षों का निर्वाचन मार्च अंत तक कर लेने का एलान किया गया है। कहानी इतनी ही नहीं है।

कहानी यह भी है कि जनसेवा के नाम पर चुनाव लड़कर जीतनेवाले इन जनप्रतिनिधियों को मेहनताना (ऑनरेरियम) कितना मिलेगा। सबसे बड़ी इकाई नगर निगम के मेयर को दस हजार रुपये प्रतिमाह, डिप्टी मेयर को नौ हजार और वार्ड पार्षदों को सात हजार रुपये। नगर परिषद के अध्यक्ष को 9,600 और वार्ड पार्षद को छह हजार। नगर पंचायत के अध्यक्ष को 8,500, उपाध्यक्ष को 7,250 और वार्ड पार्षद को पांच हजार रुपये।

कहानी यह भी कि किन्हीं-किन्हीं नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत एक-दो नहीं, तीन-तीन, चार-चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधायक जी को कितना मिलता है। लाखों में। करोड़ों की लागत से बना मुफ्त चक्रमक आवास, मुफ्त बिजली-पानी आदि-इत्यादि।



श्याम किशोर चौधरी

...और पारिवारिक पेंशन भी। इनकम टैक्स फ्री। कहानी यह भी कि भारत सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिदिन कम से कम चार सौ रु. पारिश्रमिक दे दिया है, जबकि अपनी झारखंड सरकार ने 425 रु. साप्ताहिक अवकाश के दिनों को छोड़ भी दिया जाए तो इनकी मासिक आय औसतन ग्यारह हजार से ज्यादा ही पड़ेगी। एक हालिया कहानी यह भी कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन विगत 28 जनवरी को बारामती में क्रैश में हो गया था। वे जिला परिषद के चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे। झारखंड के प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव हालांकि दलीय आधार पर नहीं होने हैं,



लेकिन सभी बड़े-छोटे दल या तो अपने-अपने समर्थित प्रत्याशी उतार रहे हैं या गठबंधन के तहत ऐसा कर रहे हैं। कुछ बड़े नेता दिल्ली से भी आकर अलहा-मशरिफा दे रहे हैं। कहानी यह भी कि एक पार्षद के पास क्या काम होता है। उसके चुनाव की क्या अहमियत होती है। उसके पास कितना बड़ा या छोटा इलाका होता है। जवाब उपर लिखा जा चुका है, इती सी नौकरी। इता सा पद। नहीं सी 'नौकरी' के लिए इतनी मारामारी। इतनी कि कई-कई बड़े-बड़े नेताओं के निकट संबंधी मैदान में उतर गये और इतनी कि कई-कई जगहों पर कई-कई वे बागी बन खड़े हो गए, जो कल तक

गलबहियाँ दिए घूमते थे। हम एक हैं, कहते नहीं अघाते थे। कहानी यह भी कि पार्षद मुहल्ले का नेता होता है, विधायक एक विधानसभा क्षेत्र का, सांसद पूरे संसदीय क्षेत्र का। यही विधायक और सांसद अपने जिस नेता को चुनते हैं, वही राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री बनता है। एंटावर पॉलिटिकल साइंस इतना ही है। कहानी यह भी कि विश्व के सबसे बड़े दल के एक जाने-माने नेता चंद्रशेखर अग्रवाल, जो धनबाद का मेयर रहे हुए थे और एमएलए/एमपी का चुनाव लड़ने की लाइन में थे, इस बार पार्टी ने उनके नाम पर ओके नहीं किया तो परम विरोधी दल में शामिल हो गए। कहानी यह भी कि अपने समर्थित प्रत्याशियों के चयन के लिए किसी दल के बड़े नेता को दिल्ली से विमान से उड़कर क्या आना पड़ता है। मुहल्ले वाले तो बचपन से अपने इलाके के नेता को जानते हैं, पहचानते हैं। उन्हें उससे नाली की सफाई करानी है। पानी सफाई लेना है, कूड़ा-कचरा जमा होने की शिकायत करनी है। और क्या काम है। इसके लिए उम्मीदवारों और उनकी समर्थन

देनेवाले दलों का इतना खर्च क्यों। मन मानता नहीं, फिर भी मान लिया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर या वार्ड पार्षद के चुनाव में जो खर्च सीमा बताई है, उतना ही खर्च हो, तो भी पांच साल के कार्यकाल में उसकी भरपाई कैसे होगी और कहाँ से होगी। यही है लोकल लेवल के चुनाव का एंटावर मैथेमेटिक्स। सालाना ढाई-तीन हजार करोड़ का बजट। कहानी यह भी कि सैकड़ों साल पहले सोने की बिड़िया रहे देश में एक ऐसा भी दौर है, जिसमें अधिसंख्य आबादी पर पांच किलो अनाज का अहसान है। और इस अधिसंख्य आबादी के वार्ड चुनाव (मुहल्ला चुनाव) के उम्मीदवार को जिताने के लिए विमान से आवाजाही। रोटी और पानी के लिए लाइन में खड़ी जनता के लिए इससे भी क्रूर मजकूर कुछ हो सकता है। जो पीने के साफ पानी को तरसता है, उसे हजार लीटर उम्टा पेट्रोल जलाकर सपने दिखाते हैं। कहानी यह भी कि अधिसंख्य आबादी का पेट भरा है, मुफ्त के पांच किलो अनाज से। भरे पेट वाले सब सह लेते हैं। इसलिए बाअदब इंतजार करें, आ रही शहर की सरकार।

Social Media Corner

सब के हक में...

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कई वर्षों से साझा मूल्यों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का आनंद ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका परमाणु समझौता पारस्परिक प्रतिबद्धता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमुख उदाहरण था। कांग्रेस-यूपीए सरकार ने इस ऐतिहासिक समझौते के विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय संसद को नियमित रूप से विधायक में लेकर अपने दृष्टिकोण में पारदर्शिता बरती। इसकी तुलना वर्तमान परिदृश्य से करें, जहां राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित व्यापक समझौते के बारे में देश को कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में उन्होंने टैरिफ को 18 प्रतिशत तक कम करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन समझौते का कोई जिक्र नहीं किया। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने समझौते के बारे में बात करने के लिए एक बाहरी मंच का इस्तेमाल किया, बिना कोई विवरण दिए।

(मिलिजार्जुन खड्गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की लाल मिट्टी में चंदन उत्पादन को प्रोत्साहित कर किसानों और आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी और सम्मानजनक आय के नए रास्ते खोलने का यह है। इससे न केवल कृषि आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि वन और भूमि संसाधनों का वैज्ञानिक एवं टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही खादी, हैंडलूम और टसर रिल्क के साथ सहयोग के माध्यम से कारीगरों को बेहतर बाजार तक पहुंच, सशक्त ब्रांडिंग और आय में उल्लेखनीय वृद्धि का अवसर मिलेगा। यह पहल आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ परंपरागत कौशल को संरक्षित करेगी और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



आखिरकार नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उपस्थिति में भारत-ईयू के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का एलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। उर्सुला ने भी इस समझौते को सभी मंदर आफ आल डील्स कहते हुए यह रेखांकित किया कि दुनिया के वर्तमान श्रेष्ठ सेंटर और इस सदी के आर्थिक पावर हाउस भारत के साथ यह एफटीए यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में पहली बढ़त दिलाएगा। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा और यह संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। इस एफटीए ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बीच भारत और ईयू को नई रणनीतिक गोलबंदी के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दी है। भारत-ईयू एफटीए के लिए बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह वार्ता थम गई। जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू की गई, जो अब अंजाम तक पहुंची है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों वैश्विक चैन के अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। भारत प्रमुखतः श्रम-प्रधान

और प्रसंस्करण आधारित वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि यूरोपीय संघ मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं, उन्नत प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति करता है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और 27 देशों के संगठन ईयू के बीच वस्तुओं और सेवाओं में कुल व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक का रहा। इसी वित्त वर्ष में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था। यूरोपीय संघ भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करीब 117.4 अरब डॉलर रहा। इस एफटीए से भारत और यूरोपीय संघ के छात्रों, कामगारों, शोधकर्ताओं और उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक गतिशील ढांचे को आकार मिला है। यह एफटीए भारत-ईयू व्यापार के लिए महज एक व्यापार का रणनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आर्थिक पुनर्व्यवस्था के रूप में भारत और ईयू के लिए बदलते वैश्विक व्यापार वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देने वाला पड़ाव है। इस एफटीए के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क शुरुआत से ही कम या समाप्त कर देंगे, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे आगामी

वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह एफटीए व्यापार, निवेश, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रक्षा, डिजिटल पहलों, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों में आपसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और नियमों पर केंद्रित है, लेकिन निवेश संरक्षण जैसे मुद्दे अलग से सुलझाए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक मुख्य स्तंभ है, जिससे संस्थागत ढांचे का समर्थन प्राप्त है और इससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अंतरिक्ष सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक और महत्वपूर्ण आयाम है, जो दशकों के तकनीकी सहयोग पर आधारित है। जहां यह एफटीए क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे खास सेक्टर में जरूरी सफाई चैन को मजबूत करेगा, वहीं मैरीटाइम सिक्वोरिटी, आर्तकवाद से निपटने और साइबर-डिफेंस में सहयोग भी बढ़ाएगा। भारत के लिए ईयू के साथ एफटीए निर्यात और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ भारत के घरेलू बाजार को बढ़ाने, मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा। इसके जरिये भारत जहां अपने कपड़ा, चमड़ा और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा सकेगा, वहीं भारतीय पेशेवरों और आईटी सेवाओं के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के दरवाजे खुलेंगे और भारतीय श्रमिकों की यूरोप में सक्रियता बढ़ेगी।

समय का ध्यान रखें

भारत को अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए सराहा जाता है, पर इसके विभिन्न राज्य एक महत्वपूर्ण और असमान जनसांख्यिकीय बदलाव से गुजर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, केरल और तमिलनाडु 2036 तक वृद्धावस्था वाले राज्य बन जाएंगे, क्योंकि उनकी बुजुर्ग आबादी क्रमशः 22 फीसद और 20 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की कामकाजी उम्र वाली आबादी 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीच वाली राह पर हैं। ये दोनों राज्य विकास और बढ़ती उम्र के दबाव के बीच संतुलन बनाकर चल रहे हैं। जवाब में, आरबीआई ने वृद्ध आबादी वाले राज्यों को बढ़ती पेंशन लागत को वहन करने के लिए अपनी सॉफ्टवेयर को तर्कसंगत बनाने और युवा आबादी वाले राज्यों को मानव पूंजी में भारी निवेश करने की सलाह दी है। लेकिन, आरबीआई की राजकोषीय सलाह में राजनीतिक निहितार्थों का कितना ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के चावजूद, दक्षिणी राज्यों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वित्त आयोग के फॉर्मल में जनसंख्या भार के चलते ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों के मुकाबले उन्हें कम मात्रा में केंद्रीय कर हस्तांतरण हासिल हो रहा है और साथ ही आगामी परिसीमान की कवायद में उनका संसदीय प्रतिनिधित्व भी घट रहा है। उधर, युवा आबादी वाले राज्यों के पास जहां विशाल कार्यबल का उपयोग करके विकास को गति देने का सुनहरा अवसर है, वहीं शिक्षा पर उनके व्यय का हिस्सा स्थिर या कम हो गया है और रोजगार की समस्या बनी हुई है। तिस पर, ये लोग ऐसे समय में कार्यबल में प्रवेश करेंगे जब मैक्यूफेडरिंग क्षेत्र में स्वचालन और उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का बोलबाला है। लिहाजा आरबीआई का श्रम प्रदान क्षेत्रों को बढ़ावा देने का सुझाव इन राज्यों को समृद्ध होने से पहले ही वृद्ध होने की आशंका के हिसाब से नाजुक बना सकता है।

Fill the gaps budget, no big bang here

The producers of castor oil cake must be pleased. No. It is not the kind which might help futures and options players. Units located in special economic zones—which produce castor cakes from indigenous seeds on indigenous machinery—are exempted from customs duty if the output is used in the domestic market. The exemption enables the viability of export units and expands the availability of fertilisers in the domestic market for producers. Budget 2026 is defined by a plethora of such surgical steps. Union finance minister Nirmala Sitharaman's ninth essay has landed between hype and hope. The budget has quelled the chorus of hype, the serenade of brass band balladeers calling for a 1991 moment. It has also cheesed off stock market punters who hoped for booster shots, and the hike in security transaction tax has worsened the business model of the get-poor-quickly motley crowd of futures and options traders. The fact is that the government, in 2025, created the impulse for consumption demand—the recast of the income tax in February, followed by the recalibration of GST rates in October. The question in the run-up to the budget was how the government would address the persistent slide of the rupee vis-a-vis the dollar, how it could stop the sell-off by foreign portfolio investors and the tepid state of foreign direct investment. Nothing clarifies strategy like a crisis, and given the history of crisis-led transformation, the expectation was for big-bang steps. Budget 2026 has chosen to play it safe, eschewing the let's-do-something itch that afflicts governments. It has stuck to its tested thesis and a fiscally prudent path. The budget aims to limit the gap between government income and expenditure to 4.3 per cent of GDP, implying gross government borrowing of around ₹17 lakh crore. The government will spend over ₹3,800 crore every day or ₹160 crore every hour on interest payments. The basic approach of the government over the past five years—in the face of reluctant private investment—has been to maintain momentum of growth by topping up the spend on physical infrastructure—the allocation for the year has been upped from ₹11.2 lakh crore to ₹12.2 lakh crore and allocation for defence modernisation has been ramped up to around ₹2.5 lakh crore. Seven new high-speed rail corridors—allocations and timelines for which are yet to be revealed—could enable connectivity and boost growth. There is also a not-so-clear idea of city clusters as economic regions with an allocation of ₹5,000 crore for five years. The question is: Can the government avoid what happened to the smart city programme?

The budget reflects an attempt to backstop economic growth and investment with interventions. Fish caught by an Indian vessel in the exclusive economic zone on the high seas, when landed in a foreign port, will be treated as an export. The time period for exporting the final product has been extended from the existing six months to one year for exporters of leather or textile garments. The entire value of biogas used in blended CNG is exempt from excise. Limits for duty-free imports of specified inputs used for processing seafood for export are hiked. Basic customs duty on specified parts used in making microwave ovens is being exempted to deepen value addition. It has chosen to address the cogs of growth by unveiling a glut of schemes—each targeting an arthroscopic approach, dealing with the specificity of a nudge rather than mega-ton propulsion. It has sought to tap into the gold rush of data centres by offering a tax holiday until 2047 to any foreign company that provides cloud services to global customers using data centres in India. It creates a new fund of ₹10,000 crore for five years to boost biopharma manufacturing. Given the global race for rare earths, the budget proposes to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu in establishing dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To promote the manufacture of chemicals, the budget moots supporting states in establishing three dedicated chemical parks via a plug-and-play model. The outlay for electronics component manufacturing increased to ₹40,000 crore and ₹10,000 crore for container manufacturing.

Budget red alert for the middle class

Revised estimate for income tax collections is about 9% less than the budgetary projection

THE most interesting data points from the Union Budget 2026-27, hidden in plain sight, are the income tax (I-T) collection numbers. Last year, the government expected to collect about Rs 14.4 lakh crore in 'taxes on income'. Some, including me, had argued back then that this was an overly optimistic projection, given that the Finance Minister had raised the I-T thresholds and the number of I-T payers would fall sharply because of that. The counterargument given by others was that India's economy was on the verge of a revival, and that would lead to big salary hikes, and push more people across the income tax threshold. As it turns out, we were right. The revised estimate for I-T collections for 2025-26 is now just Rs 13.1 lakh crore. That's about 9 per cent less than what the Budget had estimated. More importantly, I-T collections grew by just 6.2 per cent in this fiscal year, compared to 2024-25. Compare that to the 18.2 per cent and 25.4 per cent growth seen in the previous two financial years. This is especially significant when we compare it to nominal GDP growth. In 2025-26, I-T collections underperformed nominal GDP by 1.8 percentage points. In 2024-25, I-T collections outperformed nominal GDP growth by 8.4 percentage points, and in 2023-24, the growth in I-T collections was a whopping 13.3 percentage points higher than nominal GDP growth. You don't need a clearer piece of evidence to show that India's upper middle class is in deep trouble. Let me break this down a little more. I am going to assume that those with a pre-tax monthly income between Rs 1.5 lakh and Rs 3.5 lakh are 'upper middle class'. The bulk of these people would be middle managers in the corporate sector, while some would be self-employed professionals. They account for roughly 9 per cent of those who file income tax returns and contribute about 35 per cent of the total I-T collections.

Above them come the affluent, the rich and the super rich. These include senior managers, especially those in the C-suite, top-level lawyers, doctors and other professionals, startup founders and big entrepreneurs. They make up just 1.5 per cent of those who file tax returns, but account for over 50 per cent of the income tax collected by the Centre. Now, all jobs and recruitment surveys and reports tell us that 2025 has been a great year for top honchos in India Inc, and also for people running startups. This means they must have paid much higher income tax than they did last year. Despite this, if the total income tax collections have increased by just 6.2 per cent, it can only mean that the 'upper middle class' taxpayers have paid less tax than in 2024-25. This only adds to what we know anecdotally, that thousands of middle managers in India have lost their jobs, or taken pay cuts to survive.



That we are in the middle of a massive consumption downcycle is also evident from the sluggish growth in GST collections. One reason, of course, is that GST rates have been slashed sharply in the middle of 2025-26. But even if we take just the April-September period and compare it to the previous year, the growth in GST collections was less than 6 per cent. This again, is well below the average 8.8 per cent nominal GDP growth in the first two quarters of 2025-26. So, the tax data confirms what some of us have been saying — India's upper middle class is not only earning less, it is also spending less than ever before. On the other side, the same tax data proves that India's corporate sector is doing extremely well. 'Corporation tax' collections beat the budgetary estimates — the government expected to collect Rs 10.8 lakh crore in 2025-26, but is likely to get Rs 11.1 lakh crore instead. That means corporate tax collections increased by 12.3 per cent compared to 2024-25, which is more than 1.5 times the growth in nominal GDP. In other words, corporates are getting a larger share of our national income, while the upper middle class is getting a smaller chunk. Despite this, the government expects income tax payers to continue to contribute more to the exchequer than the corporate sector. Corporate taxes are projected to account for 28 per cent of the next financial year's tax revenues, while income tax is estimated to be a little more than 33 per

cent. This can only happen if there's a massive revival in white-collar jobs and salaries in 2026-27. All evidence points to the contrary — AI is likely to cause even more middle manager layoffs this year than 2025. In fact, if the government expects income tax revenues to rise, it should also expect a revival of middle-class consumption. If that were the case, GST collections should also rise, because the increased volumes would offset the reduction in GST rates. Yet, the budgetary estimate for the next financial year is that GST collections will actually fall by 3 per cent in 2026-27 compared to this fiscal. So, the government's own indirect tax estimates seem to contradict its income tax projections. The Budget happens to be a political document. Every incumbent government uses it as a fiscal tool to win elections. The Modi government is no different. Its expenditure is directed towards those who make up the electoral numbers and those who can finance electoral campaigns. Therefore, the poor are going to continue to get subsidised food, some amount of guaranteed work, and financial aid to build homes. On the other side, India Inc will continue to get tax subsidies and lucrative infrastructure projects — including the new tax sops for building data centres. Government contracts will keep India's corporate sector insulated from the decline in consumption demand that will be caused by a fall in upper-middle-class incomes.

Periods, with dignity: SC makes menstrual health a right

The Tribune Editorial: The emphasis on schools is critical. Adolescence is when menstrual stigma bites hardest and when the absence of facilities can derail education.

THE Supreme Court's recognition of menstrual health as a fundamental right under Article 21 is a long-overdue affirmation that dignity, health and equality are indivisible. By directing states to provide free, biodegradable sanitary pads in schools and to set up menstrual hygiene corners stocked with pads and innerwear, the court has pushed menstrual health out of the shadows of stigma and into the realm of enforceable rights. Menstruation has long been treated as a private inconvenience. The consequences are stark: poor access to hygiene products, unsafe alternatives, infections, absenteeism and dropouts among adolescent girls, particularly in government schools. By framing menstrual health as intrinsic to the right to life and personal dignity, the court has reframed the debate. The emphasis on schools is critical. Adolescence is when menstrual stigma bites hardest and when the absence of facilities can derail education. Hygiene corners institutionalise privacy and preparedness, while free access to sanitary napkins



recognises that affordability should not determine attendance. The insistence on biodegradable products also

aligns public health with environmental responsibility.

Yet, the SC ruling's impact will depend on execution. Many states already run pad distribution schemes, but coverage is uneven and quality inconsistent. Budgetary allocations, supply-chain reliability and monitoring mechanisms will determine whether the directive translates into real change. Teacher sensitisation, counsellor support and curriculum integration are equally vital to dismantle taboos and ensure girls are not shamed for a biological reality. Menstrual health also extends beyond schools. Migrant workers, homeless women and those in institutions and public places remain vulnerable. The judgment opens the door to a broader policy framework, across all life stages. The task is to ensure that the promise on this everyday reality of women is delivered with dignity.

The visionary man behind The Tribune

Publishing The Tribune in English was a truly courageous act

SARDAR DYAL SINGH MAJITHIA (1848-1898) was born in Varanasi in a prominent and wealthy family from Majitha village in Amritsar district of Punjab. During the 19th century, this village was notable for the fact that Maharaja Ranjit Singh had included 16 generals from three families from the village in his army between 1800 and 1849. Dyal Singh, a distinguished son of this influential village, was a philanthropist and national hero dedicated to equality, freedom, fraternity, liberalism and humanity. He was an editor, journalist, educationist, economist, writer, prominent Congress leader, Brahmo Samajist, rationalist, eloquent speaker and a man of exemplary character.

Dyal Singh has left behind a legacy that inspires pride in all. According to BK Nehru, distinguished Indian civil servant, diplomat and former President of The Tribune Trust, Dyal Singh did for North India what Raja Ram Mohan Roy, founder of the Brahmo Samaj, accomplished for Bengal in the early 19th century — leading it from the darkness of ignorance into the light of modernity. Influenced by the ideas of Surendranath Banerjee, Rai Bahadur Mulraj and JC Bose, Dyal Singh founded The Tribune to give a voice to the Indian populace and raise public awareness. The first edition of the paper was published in Lahore on February 2, 1881. It had 12 pages, priced at four annas (25 paise) per copy. The Tribune was a weekly newspaper and was issued every Saturday. Sitalchandra Mukherjee was its first editor. He was editing his newspaper 'The Indian People' from Allahabad and agreed to manage The Tribune and send editorials and articles from there. Sitala Kanta Chatterjee was appointed as the editor in Lahore. KP Chatterjee used to do the cutting-and-pasting work. Surendranath Banerjee has written: "I pursued him to start a newspaper at Lahore. I purchased for him at Calcutta the first press for The Tribune

newspaper, and to me, he entrusted the duty of selecting the first editor. I recommended late Sitala Kanta Chatterjee of Dacca (now in Bangladesh) for the post. His successful career as the first editor amply justified my choice." (A Nation in Making, Published 1931).

Dyal Singh's courage, keen insight and unwavering dedication to his purpose placed him at the forefront of those who used their wonderful pens for the nation's benefit. The founders and managers of The Tribune believed in working solely for the public good, recognising that welfare could be promoted more effectively through moderation and restraint than through harsh attacks or extremist rhetoric.

The editorial in the first issue, titled 'About Ourselves', explained the reasons and the policy of the paper. Dyal Singh wrote: "The projectors and conductors of The Tribune have no pet theories to maintain, nor any personal interests to serve through the medium of this journal. They profess simply to act for the public weal and they are conscious that the public weal is more advanced by the charity and moderation than by rancour and hard words. Our appearance in the field of journalism is to meet a crying want of this part of India namely, an English journal for representation of native opinion... The aim of The Tribune will be, as its name imports, fairly and temperately to advocate the cause of masses. In this column we shall seek to represent the public opinion of India, specially of upper India."



The main objective of The Tribune in the vision of the founder was to act as the people's mouthpiece and be the voice of the voiceless. Dyal Singh was aware that the Indian society is multi-religious religious in character. Therefore, for the cause of social harmony, national unity and progress, he underlined secularism as a fundamental principle. The first editorial took an impartial stance on religious matters: "In religious

Indians in Madras, 3,200 in Bengal and only 1,944 in Punjab. Publishing The Tribune newspaper in English was, thus, a truly courageous act.

Punjab University, Lahore, was established in 1882 due to the tireless efforts of Dyal Singh Majithia. He envisioned that it should be like the universities in Calcutta, Madras, Bombay and London. To promote this vision, he launched a movement, publishing nearly two dozen articles in The Tribune. As a result of his relentless dedication, English was adopted as the medium of instruction, which he viewed as being a crucial key to societal and national development.

After the Partition, the newspaper moved from Lahore to Shimla, then to Ambala and, finally, to Chandigarh.

On August 15, 1978, on the occasion of Independence Day, the Dainik Tribune (in Hindi) and Punjabi Tribune (in Punjabi) editions were launched. All three editions of The Tribune are published by The Tribune Trust.

The Tribune has achieved significant growth by prioritising the representation of indigenous public opinion over commercial profits. As a leading newspaper of north India, it publishes editorials and articles with a focus on public welfare issues. Its core ideals include advocating for the rights of marginalised groups, women's rights, gender equality, secularism and unity in diversity. These ideals are reflected across its English, Hindi and Punjabi publications. Indeed, all three editions of The Tribune are a valuable legacy of Dyal Singh Majithia.

After Budget and India-US trade deal, all eyes on RBI's repo rate decision

New Delhi.(Agency)

After the Union Budget 2026 and the historic India-US trade deal, all eyes are now on the three-day Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) meeting that begins from Wednesday, with the key repo rate decision on Friday.

Economists believe RBI Governor Sanjay Malhotra-led MPC is likely to pause any further policy rate cut. The Central Bank is rather set to undertake direct measures to tackle liquidity, bond stability and currency-related risks. The RBI has already lowered the repo rate by 125 basis points since February 2025 to 5.25 per cent. With inflation likely to move higher (even in the new base year series to be published starting February 12, there is little reason for moving in with further cuts, said analysts.

"With the current repo rate at 5.25 per cent, and with inflation anticipated at around 4 per cent (will wait to see if the new series changes the inflation view), the current real rate of 125 bps seems reasonable," according to a note by Yes Bank.

The RBI should stay on a pause and keep stance at "neutral" and retain its fire power in the event of any growth slump, it added. "We expect bond purchases to continue this quarter and in April-June 2026. With the FY27 Budget outlining a record high of borrowings, the central bank might prefer to be agile and nimble its money market related operations and keep borrowing costs in check," according to Radhika Rao, Executive Director and Senior Economist at DBS Bank. The RBI recently announced a series of liquidity-enhancing measures that will pump in more than Rs 2 lakh crore into the banking system to ease liquidity pressure. The Central Bank said it will use a combination of open market bond purchases, a foreign exchange swap, and a variable rate repo operation to ease liquidity conditions in the financial system.

Rupee dips after India-US trade rally; falls 22 paise to 90.54/USD

MUMBAI.(Agency)

The rupee depreciated 22 paise to 90.54 against the US dollar in early trade on Wednesday, following a sharp rally after India and the US agreed to a trade deal on suspected dollar buying by corporates and importers.

Forex traders said despite the positive sentiment post the India-US trade deal, caution still remains as there is no signed or officially released trade agreement yet - no framework text or final documentation.

At the interbank foreign exchange market, the rupee opened at 90.35 against the US dollar, then lost ground and fell to 90.54, registering a loss of 22 paise over its previous close. On Tuesday, the Indian rupee emerged as the best-performing Asian currency, registering a record gain of 117 paise or 1.28 per cent in a single trading session to settle at 90.32 against the US dollar, after India and the US agreed to a trade deal. "After Tuesday's good news the rupee was back to its own self of weakening as RBI bought dollars towards the end to take the dollar up to 90.2650," said Anil Kumar Bhansali Head of Treasury and Executive Director Finrex Treasury Advisors LLP.

Forex traders said investors are trading with caution as the India-US trade deal still awaits formalisation.

"Any sustained turnaround in FII flows will depend on greater clarity around the final structure and commitments within the deal," CR Forex Advisors MD Amit Pabari said. President Trump stated that India will end purchases of Russian crude over an undefined timeline, while increasing imports of US energy, including oil and coal, and potentially Venezuelan crude with US approval.

"Moving away from discounted Russian oil could prove challenging for India, given its long-standing commercial and strategic ties with Moscow, and may have implications for India's energy costs and external balance," Pabari added. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, was trading 0.02 per cent lower at 97.41.

HAL Shares Tank 8% As L&T, Bharat Forge Enter Race To Build Fighter Jets

New Delhi.(Agency)

Shares of defence major Hindustan Aeronautics Ltd fell as much as 8.3% to hit an intraday low of Rs 4,100 on the BSE on Wednesday after Larsen & Toubro, Bharat Forge, and Tata Advanced Systems, were shortlisted to manufacture next generation fighter jets, with the state-owned firm missing out on the list. On the flipside, L&T and Bharat Forge were trading over a percent higher.

The final winner under the Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) programme is expected to be selected within the next three months, after the shortlisted companies submit detailed commercial proposals for manufacturing prototypes of the next-generation fighter jets, was earlier reported. The shortlisting was carried out based on parameters such as technical expertise, manufacturing capability, order book position and financial strength. Bidders were required to demonstrate their ability to absorb the AMCA design, along with adequate experience in development, engineering, manufacturing, integration and testing. One of the eligibility criteria also discouraged companies with a large outstanding order book. As per the current plan, the selected company will partner with the Aeronautical Development Agency (ADA) to build five AMCA prototypes. The defence ministry has earmarked an indicative budget of Rs 15,000 crore for the prototype development phase. The eventual production order, however, is expected to be several times larger once the aircraft is successfully developed and inducted by the Indian Air Force. The AMCA programme is widely regarded as India's largest-ever military research and development initiative. The fifth-generation fighter jet is expected to form the backbone of the country's air combat capability from the mid-2030s. An initial batch of 120 aircraft is likely to be ordered.

How buying gold on an app is pushing real gold prices higher

It is not just safe haven demand or industrial demand alone driving gold and silver prices higher. A quiet shift in how people buy gold and silver is changing real-world supply and prices.

New Delhi.(Agency)

Gold and silver have been in a strong purple patch since 2025, and one of the less obvious reasons sits quietly on people's phones. As more investors buy gold and silver through apps, ETFs and digital platforms, the demand for actual physical metal has risen, helping push prices higher in the real world. Much like Virat Kohli's remarkable IPL 2016 season, when runs kept, gold and silver have stayed in form with only minor setbacks. Silver has seen a correction early in 2026, but the overall trend remained intact. In fact, if gold and silver had raced Usain

Bolt through 2025, they would have finished well ahead, with silver clocking in record time.

GOLD AND SILVER PRICES REMAIN STRONG International gold prices climbed more than 2% on Wednesday, building on their best single-day rise since 2008 in the previous session. Market action shows how firmly prices have rebounded after recent dips. Aamir Makda, Commodity and Currency Analyst at Choice Broking, said gold and silver have both recovered sharply from their recent lows. "Gold price has rebounded significantly from the bottom of 137,000 by about 12% in recent sessions and is currently trading near 153,000. On the other side, silver price is trading at 269,000 after hitting the dip of 225,805 in the previous session," he said.

Makda said gold has pulled back from key retracement levels and is approaching important resistance zones. "Immediate resistance would be at 154,215. A breakout of this level will boost the upside momentum in gold price and the next resistance would be in the range of

160,000 to 167,000," he said. On silver, he said prices have moved above major levels and a breakout could open further upside. He expects a "moderately bullish trend in gold and silver this week".

IS SAFE HAVEN BUYING ONLY



DRIVING PRICES HIGHER?

While safe-haven buying and industrial demand still matter, they no longer explain the full picture. Abhishek Kumar, Sebi RIA and Founder of Sahaj Money, said the structure of demand has changed. "This rally has sustained due to global investment inflows in the past year. While

initial interest was driven primarily by safe-haven demand, the massive surge in digital platforms and ETF assets under management has significantly amplified the upward momentum," Kumar said.

He added that industrial demand, especially for silver from green energy and AI-related sectors, provides a base, but investor flows are now the main driver.

"Industrial demand is a critical floor for silver, but the rapid influx of retail and institutional capital through liquid digital channels is now a primary catalyst," he said.

HOW DIGITAL BUYING OF GOLD, SILVER PUSHES PRICES HIGHER?

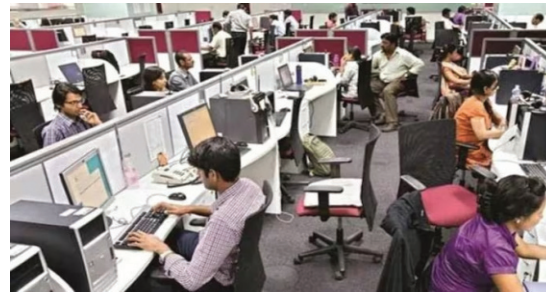
One of the key reasons app-based buying matters is that most regulated gold and silver ETFs are backed by physical metal. Kumar explained that digital buying is not just a paper transaction. Most regulated gold and silver ETFs are backed by physical gold and silver, which means the fund manager must purchase and store actual metal in a secure vault for every new share issued," he said.

AI panic sinks global tech stocks: Should Indian IT employees be worried

New Delhi.(Agency)

If you are trying to figure out why India's top IT stocks are suddenly falling together, the answer lies thousands of miles away in the United States, where an overnight wave of AI panic slammed global tech markets and sent shockwaves straight into India's IT sector. Shares of domestic IT giants Infosys, TCS, LTIM, HCLTech and Tech Mahindra were down between 5% and 8% in morning trade. Wipro slipped nearly 5%. The Nifty IT index crashed nearly 7%. The trouble began when Anthropic, one of the fastest-growing AI companies in the world, released a new set of enterprise AI tools designed to handle work that global firms often outsource to Indian IT companies. These tools claim to take over document reviews, compliance checks, back-office processing, and data-heavy operations work. These are exactly the kind of high-volume tasks that keep thousands of IT professionals busy every day. Once the

announcement hit US markets, investors quickly sold software and outsourcing stocks. Infosys and Wipro's American Depositary Receipts (ADRs), which are shares traded in the US, fell sharply. By the time Indian



markets opened, the mood was already set and the selling pressure intensified. **ARE IT JOBS AT RISK AMID AI BOOM?**

This hit the Indian IT sector at a time when it was already in a delicate position. Deal ramp-ups have been slow. Clients in the US and Europe

have been cautious with new spending. Several large deals announced last year are still stuck in transition. Valuations were stretched, demand signals were weak and one sharp global trigger was enough to push stocks lower. But behind the market chaos sits a much more immediate concern. What happens to jobs in the sector?

The anxiety is not unfounded. TCS has already reduced over 30,000 roles in the last six months to manage costs and realign itself for an AI-heavy future. Amazon is cutting thousands of corporate jobs worldwide. Meta is trimming staff in its Reality Labs division. Global tech companies are learning to operate with smaller teams as automation improves. The fear is that Indian IT firms will eventually follow the same path.

Several large deals announced last year are still stuck in transition. Valuations were stretched, demand signals were weak and one sharp global trigger was enough to push stocks lower. But behind the market chaos sits a much more immediate concern. What happens to jobs in the sector?

The anxiety is not unfounded. TCS has already reduced over 30,000 roles in the last six months to manage costs and realign itself for an AI-heavy future. Amazon is cutting thousands of corporate jobs worldwide. Meta is trimming staff in its Reality Labs division. Global tech companies are learning to operate with smaller teams as automation improves. The fear is that Indian IT firms will eventually follow the same path.

Musk's net worth soars past \$800 billion after SpaceX-xAI deal

Musk's net worth reached roughly \$852 billion, almost \$578 billion higher than the world's second-wealthiest person, Google co-founder Larry Page, whose net worth is estimated at \$281 billion.

New Dey)

US entrepreneur Elon Musk's net worth surged past the \$800 billion mark after SpaceX acquired his artificial-intelligence firm xAI, making him the richest person in history by a wide margin.

Musk's net worth reached roughly \$852

billion, almost \$578 billion higher than the world's second-wealthiest person, Google co-founder Larry Page, whose net worth is estimated at \$281 billion. The merger took the combined value of the company to \$1.25 trillion and added about \$84 billion to Musk's fortune, according to reports. Before the merger, Musk owned about 42 per cent of SpaceX which was valued at \$800 billion and roughly 49 per cent of xAI, which was valued at \$250 billion after a recent private fundraising round. Post-merger, Musk's stake in the combined entity touched 43 per cent, worth about \$542 billion and SpaceX became Musk's largest holding by a wide margin, the reports said.

Musk also retains about 12 per cent of Tesla, valued at approximately \$178 billion, along with Tesla stock options, estimated at \$124 billion. Further, in addition to these, Musk also receives a

shareholder-approved Tesla pay package up to \$1 trillion in additional Tesla stock, before taxes over the next decade and the cost of unlocking restricted share, if performance targets are met. He crossed several wealth milestones in the past four months such as \$500 billion, \$600 billion and \$700 billion, driven by SpaceX valuation gains and a Delaware Supreme Court ruling that restored his Tesla options.

Musk earlier said that SpaceX's Starship will begin delivering the much more powerful V3 Starlink satellites to orbit in 2026, with each launch adding more than 20 times the capacity to the constellation as the current Falcon launches of the V2 Starlink satellites.

It will enable launches "every hour carrying 200 tons per flight" and ultimately lifting millions of tons to orbit and beyond, Musk has shared his plan.

Why Anthropic's new AI tools rattled Wall Street's tech giants, hit Indian IT stocks

PANIC ON WALL STREET

Late last night, the Nasdaq slipped sharply as global investors reacted to a new set of enterprise AI tools released by Anthropic. These tools were not just another AI update. They were positioned to handle work that multinational companies typically outsource to Indian IT service providers. Tasks like document processing, compliance checks, operational analysis and other high-volume back office functions suddenly looked more automated than ever. The moment Anthropic's announcement landed, US investors cut exposure to traditional IT services. The sentiment hit the ADRs of Infosys and Wipro almost instantly, and by the time Indian markets opened, the selling had already gathered momentum.

WHY DID INDIAN IT STOCKS FALL? Indian IT stocks were already trading at stretched valuations. Deal ramp-ups were slow, global clients were cautious, and discretionary tech spending in the US and Europe was still weak. With so much nervousness already built into the system, even a small negative cue could have

triggered a fall. What arrived instead was a global shock, and it landed directly on a sector that depends heavily on overseas demand. Investors reacted immediately. For a sector that earns most of its revenue



from global clients, especially in the US, any sign that AI might replace traditional outsourcing creates fear. The fear may not reflect immediate reality, but markets always move ahead of fundamentals.

INVESTORS WORRIED ABOUT AI BOOM The panic does not mean the Indian IT model is obsolete. It does mean investors want to see how fast Indian firms can

adapt to the new AI era. Companies have been ramping up investments in cloud, automation and AI led services, but the market wants clarity on whether these shifts are happening fast enough to protect future revenue.

The irony is that this sector remains one of India's most globally competitive industries. Indian IT firms have the talent, scale and client relationships needed to integrate AI into their offerings. What they need now is a clear narrative that reassures investors that the next decade of outsourcing will still have India at its core. Volatility is here for a while. Every new AI announcement from global players will test market nerves. Today's fall was a reminder that sentiment around tech is extremely fragile and that Indian IT will remain highly sensitive to global news flow. This story matters because it marks a new phase in how markets view technology. AI is no longer a distant buzzword. It is influencing stock prices, investor decisions, and long-term sector expectations in real time.



Delhi used only 14% of NCAP funds to fight air pollution since 2019, lags far behind NCR cities

The disclosure came a day after the Union Budget was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman with an allocation of Rs 1,091 crore under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's "Control of Pollution" scheme for 2026-27.

New Delhi.(Agency)

Delhi has utilised only 14% of the funds so far — Rs 14.1 crore of Rs 99.77 crore — released under the National Clean Air Programme (NCAP) since 2019 even as the neighbouring cities in the National Capital Region (NCR), such as Ghaziabad and Meerut, have spent more than 80% of their funds. This city wise data was provided by Union Minister of State for Environment Kirti Vardhan Singh in a written reply to the Lok Sabha on Monday. The disclosure came a day after the Union Budget was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman with an allocation of Rs 1,091 crore under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's "Control of Pollution" scheme for 2026-27. Notably, the budget allocation under one scheme does not represent the entirety of pollution-related funding in Delhi-NCR, which is spread across multiple programmes and institutions.

What is NCAP?

Launched in January 2019, the NCAP is the Centre's framework for improving air quality in

130 cities. It sets city-specific targets for reducing particulate matter pollution, with an overall goal of achieving up to a 40% reduction in PM10 levels, or meeting national standards, by 2025-26. The programme is not implemented through a single funding source. Funds have been released based on performance, with large cities or the million-plus cities such as Delhi receiving grants through the Finance Commission, and smaller cities funded directly by the Environment Ministry.

The programme also relies on coordination across multiple ministries, with a nationwide action plan linked to schemes run by departments handling transport, energy, urban development, industry and agriculture. According to Anumita Roychowdhury, Executive Director, Centre for Science and Environment, "A convergence approach is needed... This means clearly identifying and augmenting financial allocations across multiple ministries." Meanwhile, the "Control of Pollution" scheme, administered by the Environment Ministry

since 2018-19, is intended to support pollution control across air, water and noise. A Parliamentary Standing Committee report published last March shows that the Budget Estimate for the 2025-26 financial year for the



scheme was Rs 853.9 crore. NCAP is one of the sub-components under this scheme. The Parliamentary Committee previously flagged serious concerns over the overall utilisation of funds under the "Control of Pollution" scheme. In its report on the Environment Ministry's demands for grants, the panel noted that against

a Revised Estimate of Rs 858 crore for 2024-25, actual expenditure up to January 31, 2025, was only Rs 7.22 crore.

The Ministry said spending was held up because formal approval to extend the scheme had not been granted.

Other channels

Pollution-related funding in Delhi-NCR also flows through other channels, such as the Commission for Air Quality Management, which has been allocated under the Union Budget, Rs 35.26 crore for the year 2026-27, largely for administrative and coordination functions, and funds generated through court and tribunal orders under the polluter pays principle, such as environmental compensation imposed by the National Green Tribunal. Another distinct funding stream for air pollution control in Delhi-NCR is the Environment Protection Charge (EPC), which operates separately from Union Budget allocations and NCAP funding, and applies to diesel cars and SUVs with engine capacity of 2,000 cc and above sold or registered in Delhi and the NCR.

Minor accused of man's murder in Delhi, went unknowingly to police

New Delhi.(Agency)

A minor who allegedly killed a 39-year-old man several days ago unknowingly walked into Mandir Marg police station on Monday just as police had zeroed in on his face in CCTV footage, a senior officer said on Tuesday.

The 17-year-old had gone to report the theft of a mobile phone. According to police, the minor had attacked the deceased after he allegedly tried to force himself on the minor. On Monday evening, Gulabi Bagh police received information about a body at the Railway Colony in Subzi Mandi. The deceased was identified as Sandeep Kumar Malviya, who had allegedly gone missing on January 25. The body had injury marks on the face and neck, police said. Sandeep's family had come to know that he had rented a room in Railway Colony that he would sometimes



visit. It is here that the body was found, police said. Police found CCTV footage of the deceased travelling in an auto-rickshaw with a younger person. It appeared that the two had met in Paharganj. The image of the younger individual was shared with Mandir Marg police station.

Police were surprised to find the minor at the station itself. He was apprehended, police said. "The 17-year old said that the deceased had allegedly taken him to a room in Railway Colony and asked him for sexual favours," Additional DCP (North), Sumit Jha said.

"The boy hit the deceased on the forehead with a gas cylinder and slashed his neck with a broken piece of glass. He took Rs 2,000, a credit card and mobile phone of the deceased, locked the room, and escaped," the officer said. According to police, the minor withdrew Rs 4,000 from an ATM in Ghaziabad, and bought a new mobile phone worth Rs 14,000.

Man faints on road in Outer Delhi, dies after being left unattended as passerby tries to rob him

New Delhi.(Agency)

A man who collapsed on a road in Outer Delhi's Ranhola area early Saturday died hours later, after CCTV footage revealed that a passerby allegedly attempted to steal from him instead of seeking help, police said. The incident took place around 4 am in West Delhi's Vikas Nagar. According to police, the man fell unconscious on the roadside and remained there unattended for several hours.

Preliminary assessment of the CCTV footage suggests that he may have suffered a medical emergency such as a heart attack or seizure, though the exact cause of death will be determined after the post-mortem examination, police said.

Police said the identity of the deceased is yet to be established. According to police, footage from nearby cameras shows two men arriving at the spot on a scooter soon after the man fell. One of them, seated at the rear, got off and allegedly picked up the victim's mobile phone, police said.

Police said that he later returned and searched the man's pockets, but appeared to find nothing of value. Moments later, the suspect seemed to notice a CCTV camera in the vicinity, after which he hurriedly left the scene along with the scooter driver, police said.

The unconscious man continued to lie on the road until around 8 am, when local residents noticed him and alerted the police. By the time authorities reached the spot, he was found dead, police said. The body was sent for post-mortem examination, and a case of theft has been registered. "We are scanning CCTV footage from the surrounding area and following other leads to identify and apprehend the suspects," a senior police officer said. Further investigation is underway.

City gig workers protest as part of nationwide stir, demand govt action

Protesting workers demanded urgent government intervention against what they described as rampant exploitation by digital platform companies.

New Delhi.(Agency)

Women took lead in a protest organised by the Gig and Platform Service Workers' Union (GIPSWU) at Jantar Mantar on Tuesday. Protesting workers demanded urgent government intervention against what they described as rampant exploitation by digital platform companies.

In Delhi, the workers associated with platforms such as Zomato, Swiggy, Urban Company, Zepto, Blinkit, Instamart, and Amazon participated in the protest. They demanded recognition of gig and platform workers as workers under labour laws. Their demands included enforcement of minimum wages and social security

measures and protection from arbitrary algorithmic control. Following the protest, a memorandum of demands was submitted to the PM's Office and to



the state chief ministers. GIPSWU president Seema Singh said that when she raised complaints against her work conditions, she was threatened with legal notices. She said

that the union had been struggling for over six years for the enactment of a separate law for gig and platform workers, asserting that exploitation would not stop unless a dedicated legislation was enacted.

Several women workers narrated incidents of harassment and insecurity.

Anjali, a gig worker, said she was assaulted by a customer, but instead of taking action, the company blocked her ID, cutting off her livelihood.

Another worker Mamta alleged that despite filing a complaint of sexual harassment, no action was taken by the platform, forcing her to continue working under fear.

Citing Kafka, Delhi HC orders release of former PBG man convicted of rape

New Delhi.(Agency)

Turning to The Metamorphosis by Franz Kafka, the Delhi High Court has ordered early release of Harpreet Singh, a former member of the President's Bodyguard who was sentenced to life imprisonment, along with colleague Satender Singh, for the gangrape of a college student at the Buddha Jayanti Park in the Capital in 2003.

Describing the Sentence Review Board's decision-making process as "fundamentally flawed", Justice Neena Bansal Krishna, in her order on January 30, observed that the convict, Harpreet Singh, "has been trapped by the State in the frozen image of his past criminality".

The bench said the SRB's decision to not grant Harpreet early release in 2024 and its subsequent approval by the Lieutenant Governor were "arbitrary, irrational, and contrary to the record".

Harpreet, represented by advocate Sumer Boparai, had submitted that he is a

reformed individual, who has been placed on the commendation roll, awarded certificates of recognition on at least three occasions, participated in various activities, and worked in a



diligent and disciplined manner while in prison. Turning to Kafka, Justice Krishna said, "Much like Gregor Samsa, the Petitioner, has been trapped by the State in the frozen image of his past criminality — viewed perpetually as the gigantic insect of 2003, rather than the reformed individual of 2025. The SRB, by

mechanically reiterating the heinousness of the original offence, as a constant and permanent bar to release, has refused to acknowledge that the Petitioner has successfully undergone a reverse metamorphosis: shedding the propensity for crime and earning his place back in humanity, through 25 years of exemplary conduct and discipline."

"The Petitioner's journey, from being a public servant who fell into crime to a prisoner who earned 21 years of clean conduct and multiple commendations — demonstrates that the reformatory objective of his sentence has been fulfilled."

"While Kafka's protagonist was ultimately destroyed by the alienation of those who could not see past his shell, the Constitution of India, anchored in the Reformatory Theory, forbids the State from condemning a prisoner to such eternal alienation, when the objective of correction has been achieved," the order stated.

FIR in Jalandhar row: Kapil Mishra writes to Speaker over breach of privilege

The Minister stated that the complaint filed by Iqbal Singh and the subsequent actions taken by the Punjab Police demonstrate disregard for the constitutional safeguard provided under Article 361A.

New Delhi.(Agency)

Delhi Cabinet Minister Kapil Mishra on Tuesday submitted a written complaint to Speaker of the Delhi Legislative Assembly, Vijender Gupta, seeking protection of legislative privilege in connection with the registration of an FIR by the Punjab Police on the Assembly proceedings dated January 6. In his letter, the Minister stated that the complaint filed by Iqbal Singh and the subsequent actions taken by the Punjab Police, including the registration of a criminal case, demonstrate disregard for the constitutional safeguard provided under Article 361A.

He said that these actions amounted to a serious breach of the privileges of the House and constituted interference with the functioning and authority of the

Legislature. The minister has requested the Speaker to take cognisance of the matter and refer it to the Committee of Privileges for appropriate examination and action.

Referring to events in the House, the Minister recalled that on January 6, the Delhi Assembly had witnessed disorder following alleged objectionable and derogatory remarks by Atishi, Leader of Opposition, against Sikh Gurus, leading to disruption of proceedings.

He further stated that on January 9, Chief Whip Abhay Verma informed the House that an FIR had been registered by the Jalandhar Police alleging that Mishra had uploaded a

doctored video clip of the Assembly proceedings on social media.



The minister cited a press release issued by the Commissioner of Police, Jalandhar, which stated that the video clip was downloaded from his social media handle

and that allegations of deliberate doctored registration of the FIR received wide media coverage and that copies of relevant news reports were enclosed with his letter.

Mishra has maintained that the video clip shared by him was a faithful and accurate reproduction of the proceedings of the Delhi Legislative Assembly and was therefore fully protected under Article 361A.

He argued that the initiation of criminal proceedings in connection with such publication undermines the privileges of an elected Member and amounts to an attempt to browbeat and subdue him in the discharge of his legislative duties.

Delhi Cabinet nod to free LPG cylinder scheme



New Delhi.(Agency)

Chief Minister Rekha Gupta on Tuesday said that the Delhi Cabinet has given approval to a scheme under which free LPG cylinders will be provided to beneficiaries on Holi and Diwali, adding that Rs 242 crore has been allocated for its implementation. The scheme was among the key promises made by the BJP ahead of the 2025 Delhi Assembly elections.

Under the scheme households with valid ration cards will receive an amount of Rs 853, the cost of an LPG cylinder, in their bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT) ahead of Holi, Gupta explained. "Beneficiaries under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) will be provided assistance of Rs 553 per cylinder after adjusting the central government's subsidy of Rs 300 per cylinder," she added. "I want to congratulate my sisters and the families. We made a promise of providing one free LPG cylinder each on Holi and Diwali in our (election) manifesto. Today, we passed that scheme and sanctioned Rs 242 crore for it," she said.

Stating that all households with ration cards will be eligible for the scheme, if they are currently using PNG pipelines, Gupta said: "The assistance will be provided on two occasions — Holi and Diwali — irrespective of whether the cylinder is refilled that month or not."

The estimated annual expenditure on the scheme will be around Rs 242.77 crore, and adjustments will be based on changes in price of cylinders, government subsidy, and number of beneficiaries, said officials. "This scheme not only aims at providing financial assistance, but also ensures relief during the festive season. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and through the PMUY, the Centre has provided clean fuel, better health and respectable life to people. The Delhi government's scheme is an extension of the same visionary thinking," the CM said. Gupta also said that the BJP government is fulfilling all its poll promises in a phased manner.

Meanwhile, speaking about the party's promise of providing LPG cylinders to women from poor families for Rs 500, an official said: "For this, we need an updated data of eligible candidates and set an eligibility criteria...The work on this project is underway...It will be soon implemented," said officials.

NEWS BOX

Japan Ex-PM Shinzo Abe's Killer Appeals Sentence

Japan. (Agency)

The gunman convicted of shooting dead former Japanese prime minister Shinzo Abe in 2022 has appealed his life sentence, his lawyer told AFP Wednesday. Tetsuya Yamagami, 45, was found guilty two weeks ago at the Nara District Court and jailed for life for using a homemade gun to assassinate Abe during an outdoor campaign event. "Today, I filed the motion to appeal," court-appointed defence counsel Masaaki Furukawa told AFP. Furukawa said the move was "an opportunity to correct the unjust lower-court ruling". The lawyer declined to discuss Yamagami's intentions regarding the appeal, including whether he was seeking to fight the guilty verdict or reduce the sentence. The trial will now move to the Osaka High Court in the western commercial hub, Furukawa said, adding it was not immediately clear when the appeal will begin. Abe's shooting forced a reckoning in a country with little experience of gun violence, and ignited scrutiny of alleged ties between prominent conservative lawmakers and a secretive sect, the



Unification Church.

Yamagami's case drew some public sympathy as his defence team argued that the attack was triggered by his mother's blind donations to the Church that pushed his family into bankruptcy. Abe had spoken at events organised by some of the Church's groups. The sect supported his Liberal Democratic Party in elections.

Khawaja Asif Explains Why Pakistani Forces Are "Handicapped" In Balochistan

World. (Agency)

Khawaja Asif, the Defence Minister of Pakistan, has admitted that the Pakistani security forces were "handicapped" against Baloch rebels due to the sheer size of Balochistan province as they battle a fresh surge in militant violence. His remarks came days after Baloch rebels launched simultaneous attacks across multiple towns in the volatile province, killing at least 80 security personnel and destroying more than 30 government properties.

Addressing Pakistan's national assembly, Asif described the geographical challenges faced by troops in the country's largest yet least populated province amid the serious security situation after separatist forces launched coordinated attacks across at least 12 locations, triggering one of the deadliest security crises in recent years. Authorities have said at least 177 insurgents were killed in sweeping counter-terror operations across the province.

What Khawaja Asif Said

"Balochistan constitutes over 40 per cent of Pakistan geographically... To control it is much more difficult than a populated city, and it needs the deployment of massive forces. Our troops are deployed there and are in action against them (terrorists), but they are physically handicapped by guarding and patrolling such a big area," he said. According to Pakistani authorities, at least 33 civilians and 17 members of the security forces were killed in the weekend violence.

Nukes To Minerals: What Jaishankar, Rubio Discussed After India-US Deal

Washington. (Agency)

Foreign Minister S Jaishankar, who is in Washington, met US Secretary of State Marco Rubio and discussed formalising bilateral cooperation on critical minerals exploration, mining, and processing. According to Jaishankar, several facets of the India-US strategic partnership were covered during the discussions, including trade, energy, nuclear, defence, critical minerals and technology. In a post on X, the Foreign Minister said that both leaders agreed on the early meetings of various mechanisms to advance our shared interests.

According to a statement issued by Principal Deputy Spokesperson Tommy Pigott, Rubio and Jaishankar welcomed the India-US trade deal reached between President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. "The two leaders emphasised the importance of our democracies working together to unlock new economic opportunities and advance our shared energy security goals," the statement said. "Secretary Rubio and Minister Jaishankar concluded their meeting by expressing their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. They acknowledged that a prosperous Indo-Pacific region remains vital to advancing our shared interests," the statement added. The meeting between Jaishankar and Rubio comes a day after Trump announced on Truth Social that India and the US agreed to a trade deal, under which Washington will bring down the reciprocal tariff on Delhi from 25 to 18 per cent. Jaishankar is on a visit to the United States from February 2 to 4 and will participate in the Critical Minerals Ministerial convened by Rubio on Wednesday.

Jaishankar, Rubio welcome trade deal; discuss energy, nuclear, defence, critical minerals

Jaishankar is on a visit to the United States from February 2-4 and will participate in the Critical Minerals Ministerial being convened by Rubio.

CAIRO. (Agency)

NEW YORK/WASHINGTON: External Affairs Minister S Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio "welcomed" the trade deal reached between President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi, and discussed "formalising" bilateral cooperation on critical minerals exploration and mining during their meeting in Washington DC on Tuesday.

Rubio held bilateral discussions with Jaishankar at the State Department, ahead of the inaugural Critical Minerals Ministerial meeting being convened by the US on Wednesday. "Delighted to meet US @SecRubio this afternoon. A wide ranging conversation that covered our bilateral cooperation agenda, regional and global

issues," Jaishankar posted on X after the meeting. "Facets of India-US Strategic Partnership discussed included trade, energy, nuclear, defence, critical minerals and technology. Agreed on the early meetings of various mechanisms to advance our shared interests," he wrote. A readout of the bilateral meeting provided by State Department Principal Deputy Spokesperson Tommy Pigott said that Rubio and Jaishankar "welcomed the trade deal reached between President Trump and Prime Minister Modi. The two leaders emphasised the importance of our democracies working together to unlock new economic opportunities and advance our shared energy security goals."

Pigott further said that Rubio and Jaishankar "discussed formalising bilateral cooperation on critical minerals exploration, mining and processing." Rubio and Jaishankar "concluded their meeting by expressing their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. They acknowledged that a prosperous Indo-Pacific region remains

vital to advancing our shared interests," the readout said, referring to the four-nation grouping of Australia, India, Japan and the US. In an X post, Rubio said he met with Jaishankar to "discuss our bilateral



cooperation on critical minerals exploration and work together to unlock new economic opportunities between our two countries. We also commended the trade deal between the United States and India." Jaishankar is on a visit to the United States from February 2-4 and will participate in the Critical Minerals Ministerial being convened by Rubio.

During the visit, he will also hold meetings with senior members of the US administration, the Ministry of External Affairs had said. The meeting between Jaishankar and Rubio came a day after

Trump announced on Truth Social that India and the US agreed to a trade deal under which Washington will bring down reciprocal tariff on Delhi from 25 to 18 per cent. At the inaugural Critical Minerals Ministerial, the US will welcome delegations to advance collective efforts to strengthen and diversify critical minerals supply chains. "This historic gathering will create momentum for collaboration to secure these critical components vital to technological innovation, economic strength, and national security," the State Department has said. US Vice President J D Vance, Rubio, Special Assistant to the President of the United States and Senior Director for Global Supply Chains David Copley, and Under Secretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg will deliver opening remarks at the ministerial.

India to end purchases of Russian oil, commit \$500bn investment in US: White House

NEW YORK/. (Agency)

The White House has hailed a new trade agreement with India, stating that the country has committed to no longer purchasing Russian oil, while Prime Minister Narendra Modi has also agreed to investments worth USD 500 billion across key American sectors.

The remarks were made by White House Press Secretary Karoline Leavitt on Tuesday. "The President struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship," Leavitt told reporters.

"India is committed not only to no longer purchasing Russian oil, but also to buying oil from the United States, and potentially from Venezuela as well. This will have a direct benefit for the United States and the American people," she said. Leavitt added that Prime Minister Modi had also committed to USD 500 billion in investments in the United States, including in transportation, energy



and agricultural sectors.

"So this is another great trade deal thanks to President Trump," she said.

Earlier, speaking to Fox News about the India-US trade deal, Leavitt said the two leaders had a "great call" on Monday, following which the bilateral agreement was announced. "When it comes to Prime Minister Modi, I know the President particularly enjoys their relationship and has a deep respect for the Prime Minister and for his country, India," she said. "They had a great call. It was very productive, and they struck a deal in which India agreed to stop purchasing Russian oil and to buy

more American oil, and potentially oil from Venezuela as well."

Leavitt added that Trump and his national security team are "now dictating" Venezuela's oil commerce and sales. "This directly benefits the American people. In addition, India has agreed to invest more in the United States following President Trump's call to action," she said. She further noted that India had committed to USD 500 billion in purchases of US energy, transportation and agricultural products. Leavitt said the US tariff on India would now stand at 18 per cent, while American exports to India would face zero tariffs, calling it "a great deal and a huge win for American workers, businesses and consumers".

The Trump administration had earlier imposed tariffs of up to 50 per cent on India, including a 25 per cent penalty linked to New Delhi's purchases of Russian oil.

How Saif Gaddafi, Son Of Libya's Ex-Dictator, Was Killed Inside His Home

World. (Agency)

Saif al-Islam Gaddafi, the most prominent son of the late Libyan leader Moammar Gaddafi, has been killed in an attack carried out by four assailants, according to Saudi-owned publication Al Arabiya. The 53-year-old was killed in the town of Zintan, 136 kilometres (85 miles) southwest of the capital, Tripoli. Attackers shot Saif al-Islam in the garden of his residence before fleeing the scene on Tuesday evening, a source close to the Gaddafi family told the publication. Reports claimed gunmen disabled security cameras at Gaddafi's house and shot him after a confrontation. He was killed at around 2:30 am (local time).

Details about the circumstances of the incident that claimed his life have not been fully disclosed, but one of Saif al-Gaddafi's close associates described it as an "assassination." Abdullah Othman, who was a member of the political team (2020-2021) and one of Saif Gaddafi's political advisers, confirmed his death in a Facebook post.

"We belong to God, and to Him we return. The mujahid Saif al-Islam Gaddafi is in God's care," he wrote. Saif al-Islam has remained a prominent political figure since the collapse of his father's rule in a NATO-backed uprising in 2011. The Life and Times of Saif al-Islam Gaddafi Saif al-Islam Gaddafi went from his notorious father's heir apparent to a decade of captivity and obscurity in a remote hill town before launching a presidential bid in Libya that helped derail an attempted election. Despite holding no official position, he was once seen as the most powerful figure in the oil-rich North African country after his autocrat father, Moammar Gaddafi, who ruled for more than four decades. Saif al-Islam shaped policy and mediated high-profile, sensitive diplomatic missions. He led talks on Libya abandoning its weapons of mass destruction and negotiated compensation for the families of those killed in the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland, in 1988.

Determined to rid Libya of its pariah status, Saif al-Islam engaged with the West and championed himself as a reformer, calling for a constitution and respect for human rights. Educated at the London School of Economics and a fluent English speaker, he was once seen by many governments as the acceptable, Western-friendly face of Libya. But when a rebellion broke out against Gaddafi's long rule in 2011, Saif al-Islam immediately chose family and clan loyalties over his many friendships to become an architect of a brutal crackdown on rebels, whom he called rats. Speaking to news agency Reuters at the time of the revolt, he said, "We fight here in Libya, we die here in Libya." After rebels took over the capital, Tripoli, Saif al-Islam tried to flee to neighbouring Niger dressed as a Bedouin tribesman. The Abu Bakr Sadik Brigade militia captured him on a desert road and flew him to the western town of Zintan about one month after his father was hunted down and summarily shot dead.

Culture, Trade, Trust': China Envoy Signals New Momentum In India Ties

WASHINGTON. (Agency)

China's Ambassador to India, Xu Feihong, used the occasion of the Spring Festival and Chinese New Year celebrations to underline what he called a "renewed momentum" in India-China relations, blending cultural reflections with concrete economic milestones and diplomatic signals of a reset between the two Asian neighbours. Speaking to a gathering of Chinese and Indian guests, the envoy invoked centuries-old civilisational links, drawing from his recent visits to the Ajanta Caves and Ellora Caves—UNESCO World Heritage sites known for their Buddhist art and architecture—where he said he could "see the historical exchanges and learning between Chinese and Indian Buddhist cultures."

He spoke about his recent visits to Santiniketan, home to Nobel laureate Rabindranath Tagore, and the Chinese language and culture departments at Visva-Bharati University in West Bengal. These visits, Feihong said, reinforced his sense of the "enduring cultural ties and spiritual resonance" between the two countries. Drawing parallels between traditional festivals and philosophies, the envoy noted how both nations emphasise unity, harmony, and self-reliance at the family and national levels. He suggested that China's vision of global harmony and India's aspirations for global leadership share common ground in promoting multilateralism and the development of the Global South. Feihong stressed that Beijing views New Delhi as "a cooperation partner and development opportunity," calling for better alignment of development strategies and deeper practical cooperation to "expand the pie of future benefits." He emphasised strengthening people-to-people exchanges, building "bridges of friendship," and enhancing multilateral coordination.

A key highlight of his address was the economic data. Feihong revealed that bilateral trade between India and China touched a record US\$155.6 billion in 2025, marking over 12 per cent year-on-year growth. Indian exports to China, he said, grew by 9.7 per cent, showcasing what he described as the "vast potential" of economic engagement between the two economies. The ambassador also pointed to recent steps to ease travel and exchanges. China has resumed the pilgrimage for Indian devotees to Mount Kailash and Lake Manasarovar in the Tibet Autonomous Region. India, in turn, has resumed issuing tourist visas to Chinese citizens, and direct flights between the two countries have been restored—moves he said would significantly boost people-to-people contacts.

Importantly, Feihong referred to the meeting between Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi in Tianjin last August, calling it a "successful meeting" that helped put relations on a path of improvement. Since then, he said.

Palestinians wait at border between Gaza and Egypt as uncertainty clouds reopening of Rafah crossing

KHAN YOUNIS. (Agency)

Palestinians gathered on both sides of Gaza's border with Egypt on Tuesday hoping to pass through the Rafah crossing, after its reopening the previous day was marred by delays, interrogations and uncertainty over who would be allowed to cross. On the Egyptian side were Palestinians who fled Gaza earlier in the Israel-Hamas war to seek medical treatment, according to Egypt's state-run Al-Qahera News television. On the Gaza side, Palestinians in need of medical care that is unavailable in Gaza gathered at a hospital before ambulances moved toward Rafah, hoping for word that they would be allowed to cross the other way. The office of the North Sinai governor confirmed Tuesday that an unknown number of patients and their companions had crossed from Gaza into Egypt. The bus with about 40 Palestinians that entered Gaza via Rafah on Tuesday arrived at Nasser hospital in Khan Younis early Wednesday morning, where their families welcomed them after spending the

entire day waiting. Though hailed as a step forward for the fragile ceasefire struck in October, it took more than 10 hours for only about a dozen returnees and a small group of medical evacuees to cross in each direction on the first day Rafah reopened. Three women who crossed into Gaza on Monday told The Associated Press on Tuesday that Israeli troops blindfolded and handcuffed them, then interrogated and threatened them, holding them for several hours before they were released. The numbers permitted to cross on Monday fell well short of the 50 people that officials had said would be allowed each way and barely began to address the needs of tens of thousands of Palestinians who are hoping to be evacuated for treatment or to return home. The import of humanitarian aid or goods through Rafah remains prohibited. "Not a solution to the crisis." Evacuation efforts on Tuesday morning converged around a Red Crescent hospital in Khan Younis, where a World Health Organization team arrived and a



vehicle carrying patients and their relatives rolled in from another hospital. Then the group of WHO vehicles and Palestinian ambulances headed toward Rafah to await crossing. As the sick, wounded and displaced waited to cross in both directions, health officials said the small number allowed to exit so far paled beside Gaza's tremendous needs. Two years of fighting destroyed much of its medical infrastructure and left hospitals struggling to treat trauma injuries, amputations and

chronic conditions like cancer. In Gaza City, Shifa Hospital director Mohamed Abu Selmiya called the pace "crisis management, not a solution to the crisis," imploring Israel to permit the importing of medical supplies and equipment. He wrote on Facebook: "Denying the evacuation of patients and preventing the entry of medicines is a death sentence for them." U.N. and WHO officials said the trickle of patients allowed out and restrictions on bringing in desperately needed supplies are prolonging a disastrous situation in Gaza. "Rafah must function as a real humanitarian corridor so we can have a surge in aid deliveries," said Tom Fletcher, the U.N.'s top relief official. Palestinian Red Crescent spokesperson Raed al-Nim told AP that only 16 patients with chronic conditions or war wounds, accompanied by 40 relatives, were brought from Khan Younis to the Gaza side of Rafah on Tuesday—less than the 45 patients and wounded the Red Crescent was told would be allowed.

NEWS BOX

**Boycott India, forget Super 8s:
Why rain is Pakistan's biggest
foe in Colombo**

NEW DELHI. (Agency)

Pakistan are set to boycott their group-stage match against India in the T20 World Cup 2026, but the move could prove detrimental to their own campaign. Pakistan, who are scheduled to play all their matches in Sri Lanka, might also have to contend with unpredictable weather during the tournament. The Saim Ayub-led side is set to play four group-stage matches in Sri Lanka, one of which they are already boycotting. Of the remaining three matches, two are expected to face possible rain interruptions, which could seriously hurt their chances of qualifying for the next round. Weather in Colombo has historically been unpredictable and, if even one of those two matches is washed out, Pakistan could fall behind not only in terms of points, but also Net Run Rate as well. As per AccuWeather, Pakistan's opening game against the Netherlands could see nearly a 64 per cent chance of rainfall, largely during the second half of the match. This could result in no play in the latter



stages, potentially leading to a washout. The two matches that have zero per cent chance of rainfall are the fixtures against USA and India on February 10 and 15 respectively. Pakistan lost to USA on the tricky Dallas in the previous edition of the tournament, which played a major role in their early exit.

The Pakistan government has already announced its decision to boycott the February 15 game against India. However, no official written communication has yet been submitted to the International Cricket Council. Pakistan's final group-stage match against Namibia has a 25 per cent chance of rain, meaning the game is expected to go ahead with minimal disruption. Pakistan's biggest concern will be managing their Net Run Rate in the remaining matches, given their decision to boycott India. The unpredictability of rain could make that task significantly harder. How Badly Will Pakistan's NRR be Affected.

**Gautam Gambhir
ignores question on
Pakistan's T20 World
Cup boycott vs India**

NEW DELHI. (Agency)

India head coach Gautam Gambhir avoided a question on Pakistan's boycott stance against India ahead of the T20 World Cup 2026, choosing not to comment on the sensitive issue. Gambhir was approached by reporters at the airport while departing for Mumbai, where the Indian team is set to play its first warm-up fixture against South Africa. The Indian coach first thanked the media personnel for their best wishes for the Indian team ahead of the tournament. When asked about Pakistan's refusal to play India in the upcoming World Cup, Gambhir ignored the question and continued walking without offering a response. The Pakistan government has granted its cricket team permission to participate in the tournament, but has denied approval for the side to take the field against India. The decision has triggered widespread debate, given the



financial and sporting significance of an India-Pakistan encounter at a global event. The International Cricket Council (ICC) is yet to receive official communication from the Pakistan Cricket Board (PCB) regarding the alleged boycott. However, the governing body has already warned of serious implications should the fixture not go ahead as scheduled. India, meanwhile, appear focused on their on-field preparations. The team will take on South Africa in a warm-up match as they gear up for the tournament, which begins on February 7. India and Pakistan have been drawn in the same group, alongside Namibia, the Netherlands and the USA, with their highly anticipated clash scheduled for February 15 in Colombo. Ahead of the tournament, the two sides will also feature in warm-up matches on Wednesday, February 4, with India set to face South Africa and Pakistan taking on Ireland.

**Can India defend T20 World Cup? MS Dhoni
gives his verdict on Suryakumar's team**

MS Dhoni believes India are primed for a historic T20 World Cup title defence at home. The former captain, however, warns that dew and toss conditions could still decide crunch matches.

New Delhi. (Agency)

Former India captain MS Dhoni has backed India to make history at the T20 World Cup 2026, calling Suryakumar Yadav's side the most complete and dangerous team in the tournament, while also flagging dew as the one factor that could complicate matters. Speaking at a public event, Dhoni said India have everything in place for a first-ever successful T20 World Cup title defence, but stressed that managing conditions, especially dew, will be key if they are to go all the way. "It's one of the most dangerous teams," Dhoni said when asked about India's chances of retaining the title. "You know,



they would have already started batting or bowling. But what all is needed in a good team? Everything is there." Dhoni pointed out that experience and role clarity set this Indian side apart, particularly in a format where pressure situations arrive quickly and repeatedly. "They have the experience. Especially when it comes to this format, the experience is vast. They have played under

pressure. Whoever is playing whatever roles they are playing in the team, they have been in that situation for a considerable period of time," he added.

What Dhoni warned India about in T20 World Cup

While Dhoni was careful not to jinx India's campaign, he admitted that external conditions could still swing games in a short

tournament. What worries me? Again, I hate dew. Dew changes a lot of things. So, even when I was playing, something that really scared me was dew. Where the toss becomes crucial and all of that," Dhoni said.

According to him, India's strength lies in their consistency across conditions, provided the playing field remains reasonably balanced.

"If we are playing 10 matches with some of the best teams, we will come out as winners more often than not, if the conditions remain neutral," he noted.

Are India T20 World Cup favourites?

India's recent record backs up Dhoni's confidence. Since lifting the T20 World Cup in 2024, they have not lost a single bilateral series or tournament. In this period, India have won 32 matches and lost just five, underlining their dominance in the shortest format. Zooming out further, since August 2023, India have won 49 of their 63 T20Is, losing only three. They currently sit atop the ICC Men's T20I Team Rankings and boast the format's top performers, with Abhishek Sharma ranked No.1 batter and Varun Chakaravarthy the leading T20I bowler.

India enter the 2026 edition as both hosts and defending champions, chasing something no men's team has achieved before.

**Pakistan being unfair to own players with
T20 World Cup India boycott call: Kapil Dev**

NEW DELHI. (Agency)

Former India captain Kapil Dev has issued a strong warning to Pakistan over their decision to boycott the group-stage clash against India at the T20 World Cup 2026, stating that the move will ultimately hurt Pakistan cricket more than anyone else.

Kapil said Pakistan's call to skip the February 15 India match will damage the country's reputation and harm its own players, especially youngsters aspiring to play on the world stage. Speaking to NDTV, the 1983 World Cup-winning captain stressed that such board-level decisions carry long-term consequences that players are forced to bear. "If the decision was taken by the players, they can come out and say so. But when the board decides that you will not play, the reputation of the country comes down," Kapil Dev said. "It is not looking bright for Pakistan. You are killing the generation. Pakistan have given us fantastic talents over the years, but if you don't allow these boys to play the World Cup, you are hurting the game and being unfair to your own players."

Can Pakistan boycott India T20 World

Cup match?

Pakistan announced on Sunday that while they will participate in the T20 World Cup, they will not take the field against India in



Colombo. The decision followed the ICC rejecting Bangladesh's request to move their World Cup matches out of India citing security concerns, after which Bangladesh were replaced by Scotland in the tournament. Kapil also pointed out that while the boycott may trigger emotional reactions initially, the global cricket audience will eventually move on, leaving Pakistan isolated with the fallout. "Emotions and spectators will be impacted,

but in the long run, no one will miss them. People will move on," he said.

The ICC has already expressed concern over Pakistan's stance and urged the PCB to reconsider, highlighting the potential long-term damage to the sport. As per tournament regulations, both teams must be present at the toss to avoid a walkover. Sources indicate India will travel to Colombo as scheduled, with captain Suryakumar Yadav expected to attend the toss. If Pakistan captain Salman Ali Agha fails to appear, India could be awarded two points, though further disciplinary action remains uncertain. Beyond sporting implications, the financial cost could be significant. A walkover in the India-Pakistan clash, the most commercially valuable fixture in world cricket, could reportedly result in advertising losses of up to Rs 250 crore for the host broadcaster.

For Kapil Dev, however, the biggest loss would be unseen. In attempting to make a political statement, Pakistan risk sidelining their own cricketers and setting back a generation that deserves exposure at cricket's biggest stage.

**IND v SA, T20 World Cup warm-up:
Now or never for Sanju Samson**

NEW DELHI. (Agency)

India will take on South Africa in their only warm-up match ahead of the T20 World Cup 2026 in Navi Mumbai on Wednesday, February 4. A warm-up for this Indian side? Really?

After all, this is a team that just rolled through a five-match T20I series against New Zealand, stacked with match-winners and brimming with confidence. So why the need for one final dress rehearsal before they begin their title defence against the USA in Mumbai on February 7? Because even the most ruthless winning machines have loose screws. And India, for all their depth and dominance, still have a couple of selection calls to iron out before the real business begins. Let's start with the most uncomfortable one: Sanju Samson. Once again, the wicketkeeper-batter finds himself in familiar territory — waiting, watching,



and fighting to hold on. His returns from the T20I series against New Zealand did him no favours: just 46 runs across five matches, including three single-digit scores. It is, unflatteringly, the lowest tally by an Indian opener who featured in every game of a five-match bilateral T20I

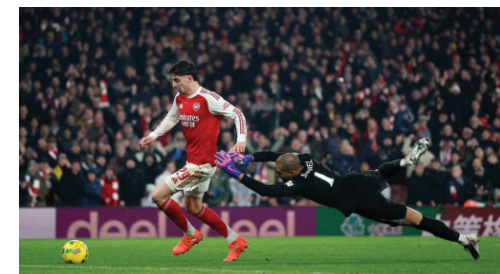
series. SAMSON VS ISHAN KISHAN

And the timing couldn't be worse.

Because Ishan Kishan has come charging in from the outside lane. A late entrant into the T20 World Cup squad, Kishan made sure he didn't arrive quietly. Against New Zealand, he piled up 215 runs at an average north of 50 and a staggering strike rate of 231.18, capping the series with a match-winning hundred in Thiruvananthapuram on Saturday, January 31. If Samson needed breathing room, he didn't get it.

His relationship with selection has long been complicated. #JusticeForSamson has trended often enough to feel like a recurring calendar event. And you don't need to rewind too far to understand why. At last year's Asia Cup, India brought Shubman Gill back into the T20I set-up and asked Samson to shift to the middle order — effectively,

defeat. We are so happy. I think overall, over the two games, we deserved to be through," Arta said in his post-match press conference. "It was a long match. We expected that. We wrapped it up at the end in a beautiful way, with Kai scoring the goal in the manner that he did and the reaction from the crowd." The match itself followed a familiar pattern. Arsenal were happy to keep the ball, manage the tempo and wait for Chelsea to make mistakes. Chelsea, to their credit, stayed organised and competitive but struggled to turn possession into clear chances. Kepa Arrizabalaga was rarely tested, with Enzo Fernandez's first-half effort from distance the only moment that briefly asked a question. The breakthrough finally arrived deep into stoppage time. Declan Rice picked out Kai Havertz with a cross, the substitute showed composure to round Robert Sanchez, and the empty net did the rest. It was a neat end to a tie that Arsenal had largely controlled across both legs. Rosenior, still early in his tenure, focused on the positives. "I think everyone can see a difference in our performances," he said. "That's really pleasing. Obviously, losing the game is not what we wanted. I've been in for less than a month, we've had eight games.

**Pakistan shouldn't play vs India, was ICC
sleeping before Former cricketer**

Former Pakistan cricketer Kamran Akmal supports PCB's decision to boycott the India match in the T20 World Cup 2026, citing ICC's biased approach. Pakistan's government has denied permission to its cricket team to play against India in the tournament.

NEW DELHI. (Agency)

Former Pakistan cricketer Kamran Akmal has slammed the International Cricket Council (ICC) for its alleged biased behaviour towards India and stated that the Pakistan Cricket Board (PCB) should not go back on its decision to not play against them in the T20 World Cup 2026. The Pakistan

government has allowed its cricket team to take part in the World Cup but has denied permission for the team to play against their arch-rivals, India.

The two teams are scheduled to face off on February 15 at the R Premadasa Stadium in Colombo. The ICC has revealed that it is yet to receive official confirmation of the boycott decision from the PCB and has warned that such a move could have serious implications for Pakistan's cricketing landscape. Amid the stand-off between the cricketing bodies, Kamran Akmal has backed the PCB's decision and questioned the ICC on whether it had turned a blind eye when India refused to travel to Pakistan in the past. "PCB should not back down. The ICC has told the Pakistan Cricket Board to reconsider its stance of boycotting the India game. Was the ICC sleeping when the Asia Cup was played under the hybrid model? Was the ICC sleeping when India said it would not play the Champions Trophy in Pakistan and would only play at a neutral

venue?" Akmal said in the Game Plan show. "How many times has Pakistan played in India despite the heightened tensions between the two countries? I have gone



myself. The ICC should have thought about these things three years ago. The two countries have not played a bilateral series for years now. Wasn't that also politics?" Akmal added. The former wicketkeeper-batter also referred to the controversial events involving the two teams during the Asia Cup 2025, claiming that India

disrespected Pakistan during the tournament. No IND vs PAK fixture to cost massive losses

"Shouldn't the ICC have thought of ending the politics then? The PCB's decision should be respected in the same way that we respected India's decision to play in a hybrid model. Things had reached extreme levels. During the Asia Cup, they refused to shake hands with our players and then refused to accept the trophy. They disrespected us," he said. India reportedly refused to shake hands with the Pakistan team throughout the Asia Cup 2025. Furthermore, India captain Suryakumar Yadav declined to receive the winner's trophy from PCB Chairman and Asian Cricket Council (ACC) President Mohsin Naqvi. The PCB chief remained adamant about handing over the trophy and eventually left the stadium with it after it was not accepted by the Indian team. Meanwhile, the absence of an India vs Pakistan fixture could result in losses amounting to nearly USD 250 million for all stakeholders involved.



Amruta Khanvilkar

Thinks Actors Get Good Roles Only When They 'Produce Or Direct'

Amruta Khanvilkar got real about the casting process in the industry, highlighting how dramatically it has changed since she started out nearly two decades ago. According to the actress, who was most recently seen in Netflix's series *Taskara: The Smuggler's Web*, factors such as social media popularity and follower counts greatly influence who should and should not be featured in a project. But she isn't too concerned about her online presence and doesn't let it affect her. "Casting is not in an actor's hands," she told *Hindustan Times*. She shared that casting an actor solely based on followers "does not make sense". Amruta asked, "How would one know if they lost a role because the other person has more social media followers?" The 41-year-old mentioned that the only way to have complete authority is to either direct or produce the specific project. Amruta explained, "If an actor wants complete control, the only way is to produce or direct. Otherwise, all you can do is focus on your craft and stay authentic."

Amruta Khanvilkar Calls The Industry "Unpredictable"

She further shared that she had now learned not to dwell on missed opportunities. Calling the industry unpredictable, she said, "If I lost a role, it was never meant to be. You win some, you lose some. That's the nature of this industry." The Raazi actress mentioned that, as actors, they should avoid being "bothered" about why they lost a role, because they might never know why makers make certain casting decisions. "Having said that, you can't live with regret," she added.

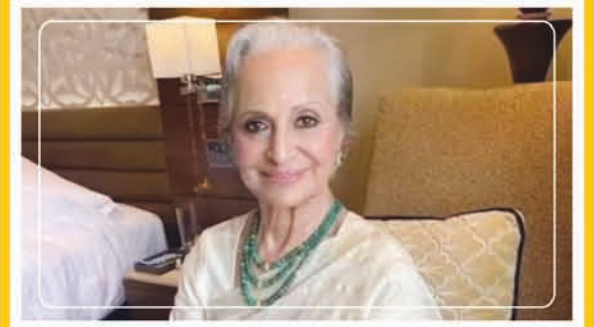
Amruta Khanvilkar Discusses The Boon Of OTT Platforms

Besides discussing changes in the casting process, Amruta also credited OTT platforms with transforming the industry for actors like her. She said that streaming services have now opened doors to a newer form of storytelling and more room to experiment than traditional media. "In long-format storytelling, especially, the writing becomes crucial. The arc, the timeline, the way characters evolve over seasons, all of that matters," she said.

She highlighted that makers are now more open to experimentation, not just with content but also with casting. And one of her favourite things about this transformation is the evolution of women-centric roles. Amruta shared that she values working with filmmakers who avoid casting female actors in typical roles. "I love it when makers treat characters as characters, not as genders. A woman can be nurturing and still be fierce. She can be in her jeans and shirt and completely k—s, and that should feel normal," she explained.



Sonam Kapoor Wishes Waheeda Rehman On Her Birthday With A Sweet Post



As legendary actress Waheeda Rehman celebrates her 88th birthday, celebrities have been pouring in warm wishes through heartfelt posts on social media. Sonam Kapoor also joined in, taking to Instagram Stories to share a special message for the iconic star. The actress posted a solo picture of the veteran star, keeping the message simple yet meaningful. Alongside the photo, Sonam wrote, "Happy birthday Waheeda ji." The post reflected Sonam's admiration for the timeless actress whose contribution to Indian cinema continues to inspire generations.

Jackie Shroff also shared a video montage on Instagram featuring pictures and clips of Waheeda Rehman. The clip also included a snippet from the iconic song *Aaj Phir Jeene Ki Tamanna Hai* from the 1965 classic *Guide*, which starred Dev Anand. In his caption of the post, Jackie simply wrote, "Warm wishes, Waheeda Rehman Happy Birthday."

Over a career spanning five decades, Waheeda Rehman has appeared in more than 90 feature films. Her contribution to cinema earned her several accolades, including the National Film Award, India's civilian awards, the Padma Shri in 1972 and the Padma Bhushan in 2011.

Sonam Kapoor's Casual Day Out

Coming back to Sonam Kapoor, the actress has been constantly making headlines for her pregnancy. She is expecting her second child with her husband, businessman Anand Ahuja. On Monday, Sonam stepped out for a casual appearance where she even interacted with the paparazzi outside a store. Acknowledging the photographers, the actress was striking some quick poses when one of them asked, "Health kaesi hai aapki (How's your health)?" Smiling at him, the actress replied, "Sab theek hai (Everything is fine), thank you." Later, Sonam also obliged some fans' requests, posing for a selfie one of them.

Sonam Kapoor's Second Pregnancy

Sonam announced her second pregnancy last year in November by sharing a post on Instagram. Sharing a series of pictures where she revealed her baby bump, the actress simply wrote, "Mother," subtly expressing her excitement. In the photos, she wore a hot-pink pure wool suit featuring oversized padded shoulders. The post confirmed her due date is Spring 2026. Sonam and Anand got married in May, 2018, in a traditional ceremony. Four years after tying the knot, the couple welcomed their first child, son Vayu, in August 2022.

Mahima Chaudhry's Daughter Arina Clicks Photos With Sidharth Malhotra, Shanaya Kapoor



It was a night of glitz and glamour in Mumbai on February 1, as captured in a recent post by Mahima Chaudhry's daughter, Arina. The star kid attended a launch event with her mother, which saw Bollywood's biggest names in attendance. Celebrities spotted at the event included Salman Khan, Twinkle Khanna, Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Sidharth Malhotra, Arjun Kapoor, Isha Koppikar, Diana Penty, and Lulia Vantur. Also lighting up the red carpet were Rohit Saraf, Mrunal Thakur, Mahima Chaudhry, Rakul Preet Singh, Jacky Bhagnani, and several others.

Now, Arina has shared exclusive glimpses and special moments from the glamorous evening. Taking to Instagram, she posted a carousel of pictures featuring several celebrated Bollywood personalities.

Arina was seen posing with Sidharth Malhotra in one photo, while another showed her interacting with Shanya Kapoor. As expected, social media users bombarded the comments section of the post with their sweetest reactions. The Internet community also talked about Arina's resemblance to her mom.

"No doubt Arina is super cute," read a comment. "So elegant, so poised—each one shining in their own way. Beautiful energy, beautiful moment," a fan wrote. Meanwhile, one of them commented, "She can be a great model."

Salman Khan, Akshay Kumar, Aamir Khan And Ajay Devgn Come Together For The Cover

The highlight of the launch was the unveiling of *Variety India's* inaugural cover on February 1. The cover features Akshay Kumar seated on a couch, with Salman Khan, Aamir Khan, and Ajay Devgn standing behind him. *Variety* described the quartet as "Unshakable. The superheroes that broke the rules of stardom," a line that perfectly captures their decades-long influence on the Hindi film industry.

Sai Pallavi

In Talks For Kalki 2 After Deepika Padukone Exit, CONFIRM Makers: 'She'll Be Perfect'

Speculation around casting changes in big-budget franchises is nothing new, but the latest buzz around *Kalki 2898 AD* has clearly struck a chord with fans. With anticipation for the sequel building, fresh rumour suggests a key role may see a new face, even as the makers remain tight-lipped. Sources close to the film have now confirmed to *Hindustan Times* that Sai Pallavi is being considered for an

important part in the sequel, following Deepika Padukone's exit from the project. While nothing has been officially announced, the development has renewed interest in what lies ahead for the ambitious sci-fi universe created by director Nag Ashwin.

Deepika's exit. They think she'll be a perfect fit for the role," the source said. At the same time, they dismissed reports claiming that Sai Pallavi has already been signed on or that filming is set to resume soon. "All these are just rumours because nothing has been finalised yet. Please wait for official confirmation."

Deepika Padukone's exit from the sequel first came to light in September 2025. Around the same time, she also stepped away from *Spirit*, directed by Sandeep Reddy Vanga. Reports claimed that she had shot for nearly 20 days for the *Kalki* sequel before leaving due to a fee-related issue. Neither Deepika nor the makers have commented on these reports. In the first film, Deepika played SUM-80, also called Sumati, a pregnant test subject in Project K and the prophesied mother of *Kalki*. Her character was central to the story.

In the Telugu version, the role was dubbed by Sobhita Dhulipala. After escaping from Supreme Yaskin's lab, SUM-80 is protected by Amitabh Bachchan's character, Ashwatthama.

Produced by Vyjayanthi Movies, the sequel is expected to continue exploring these storylines, making the casting of SUM-80 a crucial decision. With Sai Pallavi now reportedly in the mix, fans are eager to see how the role may evolve, should the casting be confirmed.



A representative associated with the film told HT that discussions are still at a preliminary stage. "Nothing has been finalised yet. But yes, the makers are looking at Sai to play SUM-80 after

important part in the sequel, following Deepika Padukone's exit from the project. While nothing has been officially announced, the development has renewed interest in what lies ahead for the ambitious sci-fi universe created by director Nag Ashwin.

